https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

17 'पूरा प्रदेश परिवर्तन का मन बना चुका है'

वर्ष-12, अंक-02, 16-31 जनवरी, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'विमुद्रीकरण ने कालेधन, जालीनोट एवं माओवादी-आतंकवादी गतिविधियों पर किया करारा प्रहार'

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने लहराया परचम

विमुद्रीकरण: बीते दो महीनों पर एक नजर

भीम मोबाइल ऐप लॉन्च

नई दिल्ली में संपन्न भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दृश्य

BJP NATIONAL EXECUTIVE MEETING
06 - 07 JANUARY, 2017
NEW DELHI

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

15 **'गरीबी से लड़ना है, तो गरीब को ताकतवर बनाना होगा'**
संगठन के लोगों को हर वक्त तलवार की धार पर चलना होता है। संगठन में काम करने वालों पर दोहरा दवाब होता है। हमें यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में नीचे से ऊपर...

वैचारिकी

जीवन का ध्येय 23

श्रद्धांजलि

नहीं रहे सुंदरलाल पटवा 25

लेख

विमुद्रीकरण: बीते दो महीनों पर एक नजर 28

औपनिवेशिक परंपरा की समाप्ति है बजट सुधार संबंधी घोषणा 30

अन्य

'ऐतिहासिक फैसले हैं नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक' 06

भारत का नेतृत्व सीमाओं और हितों की रक्षा दृढ़ता और इच्छाशक्ति से करने को दृढ़प्रतिज्ञ 09

एक साहसिक कदम- गरीब कल्याण की ओर 12

सिंगापुर के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि संशोधित 22

'ऑनलाइन भुगतान करने की जागरूकता तेज़ी से बढ़ी' 26

'उत्तराखंड विकास के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहता' 27

पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा, मतगणना 11 मार्च को 31

प्रत्यक्ष करों में 12.01 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों में 25 प्रतिशत की वृद्धि 33

संगठनात्मक गतिविधियां

17 **'पूरा प्रदेश परिवर्तन का मन बना चुका है'**
2 जनवरी को लखनऊ स्थित रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐसा जनसैलाब उमड़ा...

19 **स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने लहराया परचम**
चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा और अकाली गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर कांग्रेस...

सरकार की उपलब्धियां

20 **किसानों, गरीबों और गर्भवती महिलाओं को भारी राहत**
नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने...

32 **भीम मोबाइल ऐप लॉन्च**
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को लकी ग्राहक योजना और डिजीधन योजना की शुरुआत की। दिल्ली के तालकटोरा...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सभी लोगों को एक घर होना चाहिए। हम 'सभी को आवास' मुहैय्या कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

@AmitShah

भाजपा ने फरीदाबाद के स्थानीय निकायों के चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। इसने 40 सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की है। देशवासी विमुद्रीकरण अभियान को लगातार समर्थन बनाए हुए हैं।

@SushmaSwaraj

प्रधानमंत्रीजी- 31 दिसंबर 2016 के आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए धन्यवाद। आपने पूरी स्पष्टता, संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ अपने विजन को प्रस्तुत किया है।

facebook

31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं में 'गांव, गरीब, किसान' और समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। मैं प्रधानमंत्री को लोकहितकारी निर्णय के लिए बधाई देता हूं।

- राजनाथ सिंह

इस साल जीएसटी लागू होने पर अप्रत्यक्ष कर प्रशासन बेहतर होगा तथा यह कर चोरी के खिलाफ प्रभावकारी कानून होगा।

- अरुण जेटली

लांच होने से एक सप्ताह के भीतर 'भीम' एप 70 लाख से ज्यादा डाउनलोड हुआ तथा इससे 10 लाख ट्रांजेक्शन भी हुआ।

- पीयूष गोयल

साभार: दैनिक जागरण

साभार: राजस्थान पत्रिका

पाथेय

हमारी विचारधारा हमारी असली शक्ति है। हम इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते और न ही इससे विचलित हो सकते हैं, किन्तु विचारधारा कठमुल्लापन से भिन्न होती है। विचारधारा उन्नति की दिशा में ले जाती है किन्तु कठमुल्लापन हमें पीछे रोके रखता है। विचारधारा एक परिमाप होती है, जिसमें अपने मूलभूत सिद्धांतों से समझौता किये बिना समसामयिक मुद्दों को निरंतर बैठाना पड़ता है।

-कुशाभाऊ ठाकरे

'विकास' की राजनीति करती है भाजपा

नये वर्ष का शुभारंभ भारत में एक नये आत्मविश्वास एवं आशा के साथ हुआ है। एक ओर जहां 500/– एवं 1000/– रुपये के विमुद्रीकरण की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को समाप्त हुई, वहीं 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र को संबोधन से पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। विमुद्रीकरण के ऐतिहासिक निर्णय को कांग्रेस एवं विपक्ष के एक वर्ग के विरोध के बावजूद अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ। विमुद्रीकरण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने से आलोचकों का ना केवल मुंह बंद हो गया है, बल्कि आने वाले दिनों में इस साहसिक निर्णय का जबरदस्त लाभ इस देश के गांव, गरीब एवं किसानों को मिलने जा रहा है। इसका सबसे पहला उदाहरण बैंकों में जमा भारी धनराशि है, जिससे ब्याज दरों में कमी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गरीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने जन–जन को काला धन एवं भ्रष्टाचार से लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए बधाई दी है। इस देश की जनता की इच्छाशक्ति को प्रणाम किया जाना चाहिए, जो काला धन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री के निर्णायक कदम को सफल बनाने के लिए अनेक कठिनाइयों के बाद भी एकजुटता से नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ी रही।

जनवरी 2017 के प्रथम सप्ताह में संपन्न भाजपा कार्यकारिणी बैठक ने यथास्थितिवादी व्यवस्था से देश को बाहर निकाल परिवर्तनकारी निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए दृढ़ संकल्प प्रस्तुत किया है। विमुद्रीकरण का स्वागत करते हुए गरीब एवं शोषित–वंचित वर्गों के कल्याण के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति व्यक्त की गई है। केन्द्र सरकार के साहसिक निर्णयों की प्रशंसा करते हुए कार्यकारिणी ने महसूस किया कि विश्व में अब भारत की छवि निखर कर सामने आई है। आज प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हाल में हुए 'सर्जिकल स्ट्राईक' की भूरी–भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद के प्रति 'जीरो–टॉलरेंस' के साथ दो–दो हाथ कर रहा है। साथ ही, उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण से काला धन, नकली नोट, आतंकवाद, माओवाद एवं ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। अपने समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का संकल्प दोहराया, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को गरीबों की सेवा में प्राण–पण से जुट जाने का आह्वान किया।

> एक ओर जब अन्य राजनैतिक दल परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण एवं वोट–बैंक के गुणा–भाग में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा, गरीबों, आदिवासियों, दलितों, युवाओं एवं महिलाओं के कल्याण के लिए 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस' के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में देश अपने नये भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने को तत्पर है और विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है।

देश के विभिन्न भागों में हाल ही में संपन्न चुनावों में भाजपा को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ है। लोकसभा के लिए हुए उपचुनावों, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं में हुए उपचुनावों से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा ने भारी जनसमर्थन प्राप्त किया है। यदि इन संकेतों को माना जाए तो इसमें कोई शंका नहीं है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड एवं मणिपुर में होने वाले चुनावों में भाजपा जनता की पसंद बनकर उभरेगी। उत्तर प्रदेश में जनता विकल्प की तलाश में है, ताकि वह सपा–बसपा के गुंडाराज, भ्रष्टाचार एवं पिछड़ापन से प्रदेश को निकाल सके। उत्तराखंड में लोग हरीश रावत सरकार के भ्रष्टाचार कुशासन से ग्रस्त हैं। गोवा में निस्संदेह लोग पुनः भाजपा सरकार चुनेंगे, जबकि पंजाब में अकाली दल–भाजपा सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उत्तर–पूर्वी राज्य मणिपुर में भाजपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। वर्तमान समय में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जो सुशासन, विकास एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति को प्रतिबद्ध है।

एक ओर जब अन्य राजनैतिक दल परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण एवं वोट–बैंक के गुणा–भाग में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा, गरीबों, आदिवासियों, दलितों, युवाओं एवं महिलाओं के कल्याण के लिए 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस' के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में देश अपने नये भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने को तत्पर है और विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। इसका परिणाम है कि हर ओर भाजपा को अभूतपर्व जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

ऐतिहासिक फैसले हैं नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 6 एवं 7 जनवरी 2017 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सारगर्भित एवं प्रेरक अध्यक्षीय भाषण दिया। बैठक में सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित हुए। पहला, राजनीतिक एवं दूसरा आर्थिक। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी समापन भाषण दिया। इस बैठक में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने नोटबंदी की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। नोटबंदी कालेधन और जाली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। इसे अपार जनसमर्थन मिला। श्री शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से भारत का कद बढ़ा है। हम यहां श्री अमित शाह के अध्यक्षीय उद्बोधन का संपादित मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं :

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कहा कि कालीकट की नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे पूरे देश की जनता मन से पार्टी और सरकार के साथ जुड़ गई है। उरी में कायराना हमले के बाद देश भर में हताशा और निराशा का माहौल था। देश की जनता आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री और सरकार की ओर देख रही थी, क्योंकि उन्हें केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सख्त क़दमों की अपेक्षा थी। 2014 के लोक सभा चुनावों के दौरान हमने देश की जनता को यह भरोसा

दिलाया था कि यदि केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में भाजपा की सरकार बनती है तो देश की सीमा और वीर जवानों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार थी। प्रधानमंत्री जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सेना के वीर जवानों के अप्रतिम शौर्य के फलस्वरूप आजाद भारत में पहली बार दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया गया।

हमने जो कहा था, करके दिखाया। इस एक निर्णय से दुनिया भर में भारत को देखने का नजरिया बदला। इससे दुनिया भर में एक मजबूत संदेश गया कि हम दुनिया के अन्य देशों के साथ-साथ पड़ोसियों से भी शान्ति और समभाव चाहते हैं, लेकिन सीमा की सुरक्षा के प्रति हम समर्पित भी हैं और वचनबद्ध भी। हम सीमा पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते।

सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति देश की जनता के सामने आई। कोई खून की दलाली की बात कर रहा था तो कोई इसके सबूत मांग रहा था पर देश की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सेना की वीरता के साथ खड़ी रही।

श्री शाह ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने इतने बड़े पैमाने पर विमुद्रीकरण का फैसला लेकर देश की 86% चलन की मुद्रा को ख़त्म करने का फैसला नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवम्बर, 2016 को विमुद्रीकरण का जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उससे एक झटके में ही जाली नोटों के कारोबार, आतंकवाद, ड्रग्स, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार के साथ-साथ चुनाव से काला धन के प्रभाव को सीमित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद विपक्ष की जो नकारात्मक सोच देश की जनता के सामने आई, उससे विरोध करने वाले खुद एक्सपोज हो गए। विपक्ष ने तमाम हथकंडे अपनाकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन देश की जनता कष्ट सहने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ एकजुट हो खड़ी रही। 8 नवम्बर के पहले ये विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री जी से पूछा करते थे कि प्रधानमंत्री ने काले धन के लिए क्या किया, 8 नवम्बर के बाद यही विरोधी पार्टियां यह कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने काले धन को ख़त्म करने के लिए यह क्यों किया? फैसले ऐसे लेने चाहिए जो लोगों के भले के लिए हों, न कि लोगों के अच्छे लगने के लिए। लोगों को तकलीफ हुई, हमें भी इसका आभास है लेकिन दीर्घ काल के लिए देश के विकास के लिए यदि कोई अच्छा काम हो तो थोड़ी कठिनाइयां भी होंगी। विमुद्रीकरण का फैसला देश हित में लिया गया फैसला है, इसी की नींव पर एक विकसित भारत का निर्माण संभव हो सकेगा। 8 नवम्बर के बाद देश में जितने भी सर्वे हुए हैं, उन सभी सर्वे में एक बात साफ़ है कि देश की लगभग 75 फीसदी से अधिक आबादी विमुद्रीकरण के फैसले के साथ है।

उन्होंने आगे कहा कि विमुद्रीकरण के फैसले के बाद देश भर में जहां कहीं भी चुनाव हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट, ज्यादा सीटें और ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है। विमुद्रीकरण का फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। केंद्र में सरकार बनते ही पहले दिन से ही काले-धन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को लेकर मोदी सरकार एक्टिव मोड में थी। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार काले-धन की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और डेढ़ महीने में ही सारी जानकारियों को एसआईटी को जांच के लिए सौंप दिया गया। बैंकों में 25 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खुलवाये गए। फिर ओपन डिक्लेरेशन स्कीम लाई गई, फिर ब्लैक मनी एक्ट, बेनामी संपत्ति और डीटीएए जैसे प्रावधान किये गए। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देश चलाने के लिए नहीं, बल्कि देश को बदलने के लिए, देश की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है।

> दुनिया के किसी भी देश ने इतने बड़े पैमाने पर विमुद्रीकरण का फैसला लेकर देश की 86% चलन की मुद्रा को ख़त्म करने का फैसला नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवम्बर, 2016 को विमुद्रीकरण का जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उससे एक झटके में ही जाली नोटों के कारोबार, आतंकवाद, ड्रग्स, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार के साथ-साथ चुनाव से काला धन के प्रभाव को सीमित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि हम यदि चाहते हैं कि गरीबों को शुद्ध पीने का पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, दो वक्त का खाना मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो बजट को आगे ले कर जाना होगा, इसे बढ़ाना होगा। हम यदि चाहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और सबसे अत्याधुनिक सेना बने तो इसके लिए एक बड़े बजट की जरूरत है। हिन्दुस्तान के युवाओं को आरएंडडी (R&D) के लिए धन मुहैय्या कराने की जरूरत है। देश को यदि आगे लेकर जाना है तो हमें पैरेलल इकॉनमी को ख़त्म करना होगा और इसी प्रयास का नाम है विमुद्रीकरण। देश में पैरेलल इकॉनमी की स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ इस फैसले को लेकर देश की जनता के बीच जाएँ। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के साथ है। देश का गरीब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करने के लिए तहेदिल से तैयार है।

उन्होंने कहा कि लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, वे काले-धन के समर्थन में खड़े हैं। आज वे देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जनता ने उन्हें चिह्नित कर लिया है। हम गौरवान्वित हैं कि ये दोनों फैसले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं। (सभी कार्यकर्ताओं

ने खड़े होकर इस ऐतिहासिक फैसले के लिए करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का स्वागत किया और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया।) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को लेस-कैश सोसायटी बनाने के लिए एक-के-बाद-एक फैसले करके हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, अब दृढ़ता के साथ देश को विकास-पथ पर आगे ले जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि भीम (BHIM) एप का हर जगह स्वागत हुआ है। जन-प्रतिनिधि और पदाधिकारी जनता को इसका उपयोग करने को प्रेरित करें। यदि चुने हुए जन-प्रतिनिधि लेस-कैश के अभियान को गति देंगे तो देश की अर्थक्रान्ति का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के सिर बंधेगा। टैक्स चोरी को ख़त्म करने से हम विकास में पीछे छूट गए देश के गरीबों को ऊपर उठाने में सफल हो पायेंगे।

उन्होंने कहा कि कालीकट के अधिवेशन के बाद देश भर में हुए उप-चुनावों और स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित विजय श्री हासिल हुई है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा – हर जगह हमें जीत हासिल हुई है। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद हर चुनाव में देश की जनता ने हमें और मजबूत कर आगे बढ़ने का मौक़ा दिया है, यह बताता है कि देश की जनता विमुद्रीकरण के फैसले के साथ खड़ी है। कालीकट के अधिवेशन के बाद केंद्र सरकार ने कई निर्णायक एवं विकासोन्मुखी फैसले किये हैं, जैसे रेल बजट का आम बजट में विलय, फसल बीमा का इम्प्लीमेंटेशन, जीसैट – 18 का प्रक्षेपण, मानवरहित रुस्तम विमान का परीक्षण, नौसेना और थल-सेना का आधुनिकीकरण, रूस, जापान, सिंगापुर के साथ महत्त्वपूर्ण समझौते इत्यादि। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने भी इस दौरान अच्छा काम किया है, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में नमामि नर्मदे, महाराष्ट्र में प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम, हरियाणा में सस्ते घर की योजना, असम में काजीरंगा वन क्षेत्र को खाली कराने की योजना, गोवा में शत-प्रतिशत कैशलेस ट्रांजेक्शन का लक्ष्य इत्यादि। पंजाब, कश्मीर, झारखंड – सभी राज्यों ने सराहनीय काम किया है।

केंद्र सरकार ने कई निर्णायक एवं विकासोन्मुखी फैसले किये हैं, जैसे रेल बजट का आम बजट में विलय, फसल बीमा का इम्प्लीमेंटेशन, जीसैट – 18 का प्रक्षेपण, मानवरहित रुस्तम विमान का परीक्षण, नौसेना और थल-सेना का आधुनिकीकरण, रूस, जापान, सिंगापुर के साथ महत्त्वपूर्ण समझौते इत्यादि।

उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के 50 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर को गरीब-कल्याण योजना का पहला चरण प्रस्तुत किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का पूरा ख़याल रखा गया, किसानों के लोन को दुगुना कर 42,000 करोड़ किया गया, दो महीने का ब्याज भी माफ़ किया गया, हाउसिंग लोग सस्ता किया गया। प्रधानमंत्री की अपील पर देश के लगभग सभी सरकारी बैंकों ने 1% ब्याज दर की कटौती की जो कि काफी महत्त्वपूर्ण है।

संगठनात्मक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंडल से लेकर राज्य स्तर पर संगठन के दृष्टिकोण से काफी उत्तम प्रयास हुए। मंडल में 87%, जिला में 97% और राज्य स्तर पर शत-प्रतिशत कार्यसमिति की बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोहों के लिए पूर्णकालिक सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की अपील की थी, उस दिशा में भी काफी सफलता प्राप्त हुई है। 15 दिन के लिए 1 लाख 60 हजार से अधिक कार्यकर्ता पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे जबकि 6 महीने और साल भर के लिए क्रमशः 17696 और 2031 पूर्णकालिक सदस्य पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक पार्टियों का भी आह्वान किया कि देश में सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, ताकि चुनाव खर्च को कम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक समिति गठित की है, यह समिति एक प्रारूप बनाकर देश के फलक पर इस बहस को आगे बढ़ाने का काम करेगी और चुनाव सुधार की बहुत बड़ी परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए भी आह्वान किया है। पार्टी ने इसके लिए भी एक कमिटी गठित की है, इससे देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा और व्यापक बदलाव होंगे। यह एक महत्त्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री जी की अपील पर राजनीतिक दलों का तो जो भी रिएक्शन हो, लेकिन देश की जनता का भरपूर समर्थन प्रधानमंत्री जी के आह्वान को प्राप्त है।

आगामी पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्त्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर सरकार ने राज्य की जनता को परेशानी में डाल रखा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, हमने पूरे दम-ख़म के साथ मणिपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, संगठन को मजबूत किया है और इस बार हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में हैं। हम एक बंद-मुक्त और विकास-युक्त मणिपुर का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री जी की रैलियों का और परिवर्तन-यात्रा का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। उत्तर प्रदेश में खराब और बदहाल क़ानून-व्यवस्था, जमीनों पर अवैध कब्जे एवं गुंडागर्दी मुख्य मुद्दे होंगे। यूपी चुनाव में और चुनाव विकास पर लड़े जायेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि पाँचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय हासिल करेगी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में हम भारत को विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल हों और देश को महान बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें, इन्हीं आशा एवं विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय! ■

भारत का नेतृत्व सीमाओं और हितों की रक्षा दृढ़ता और इच्छाशक्ति से करने को दृढ़प्रतिज्ञ

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 6 एवं 7 जनवरी 2017 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया।
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हाल ही में ख़त्म हुए वर्ष में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने दुनिया के दस सबसे लोकप्रिय नेताओं ने उनका नाम शामिल किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह स्पष्टतापूर्वक स्वीकार करती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता को जनता ने उनके परिवर्तनकारी नीतियों एवं कार्यक्रम के कारण उनकी स्वीकार्यता को अतुलनीय लोकप्रियता के साथ स्वीकार किया है। हम यहां प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं...

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारत एवं दुनिया भर के लोगों को नववर्ष 2017 पर अपनी शुभकामनायें प्रेषित करती हैं। हम देशवासियों को एक ऐसा नया साल देने का वादा करते हैं, जो कि देश में और अधिक प्रगति तथा सम्पन्नता लायेगा।

राष्ट्रीय कार्यकारणी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं कैबिनेट के उनके सहयोगियों को हाल ही खत्म हुए वर्ष 2016 के दौरान सरकार की परिवर्तनगामी पहलों के लिए बधाई देती है। इन पहलों के चलते गरीब और कमजोर लोगों के जीवन में एक नई रोशनी का संचार हुआ है एवं अर्थव्यवस्था को सही दिशा पर लाकर देश के सभी वर्गों का भी भला हुआ है।

सर्जिकल स्ट्राइक : आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

हमारे सशस्त्र बलों द्वारा अचूक तरीके से अंजाम दी गयी सर्जिकल स्ट्राइक्स ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का नेतृत्व आज एक ऐसी सरकार कर रही है जो कि उसकी सीमाओं और हितों की रक्षा पूरी दृढ़ता और इच्छाशक्ति से करने को दृढ़प्रतिज्ञ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रीमंडल को हमारे उदंड पड़ोसी देश की आतंकवादी गतिविधियों का माकूल जवाब देने के लिए बधाई देती है। यह स्ट्राइक्स कितनी प्रभावी रही है इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ हफ़्तों से भारत पाक–सीमा पर शांति छाई है एवं खुद पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की पहल की है। भारत में सदा से ही पाकिस्तान समेत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण एवं दोस्ताना सम्बन्ध रखने की इच्छा का प्रदर्शन किया है। प्रधानमन्त्री मोदी जी का सूत्र वाक्य 'सब-साथ बढ़े' हिन्द महासागर के सभी पड़ोसियों के संयुक्त एवं एकीकृत भविष्य का सपना देखता है। इसलिए यह पाकिस्तान एवं दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के हित में होगा कि नवाज शरीफ सरकार पाकिस्तान पर जमीन पर चल रही आतंकी शिविरों एवं आईएसआई जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा उन्हें पहुंचाई जा रही मदद का अंत करने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाये।

आज प्रजातान्त्रिक विश्व में आतंकवाद को एक महामारी के बतौर देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान अभी भी उसका इस्तेमाल एक राजकीय नीति के बतौर करता है। वह भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करता है। आतंवादी हमले करता है तथा जम्मू और कश्मीर में हिंसक अलगाववादी आन्दोलन का सहयोग करता है। प्रधानमंत्री

द्वारा करायी गयी सर्जिकल स्ट्राइक एवं अलगाववादी षड्यंत्र का जम्मू कश्मीर एवं भारत की जनता तथा सरकारों द्वारा पूर्ण निषेध पाकिस्तान को स्पष्ट सन्देश देता है कि उसके घृणित मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आतंकवाद पर 'कोई समझौता नहीं' की नीति का अनुसरण करती है तथा इस तरह की धमकियों का उपयुक्त एवं अपारंपरिक जवाब देने का को दृढ़ प्रतिज्ञ रखती है।

अन्त्योदय

राष्ट्रवादी आन्दोलन के विचारधारात्मक प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की अवधारणा से प्रेरित होकर मोदी सरकार ने गरीबों ,उत्पीड़ितों, किसानों, दिहाड़ी मजदूरों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों की भलाई तथा कल्याण के लिए अनगिनत पहलकदमियां की हैं। इस मामले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री का भाषण सोने पे सुहागा था, जिसमें शहरी तथा ग्रामीण गरीबों, गर्भवती महिलाओं, छोटे तथा मंझोले उद्योगों एवं वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए कई रियायतें घोषित की गई। इन नई रियायतों का फायदा न सिर्फ गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों को होगा, बल्कि समाज के अन्य तबकों को भी मिलेगा क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को तीव्र रूप से गतिमान करेगा। सबको आवास सुलभ कराने में इससे विशेष फायदा होगा, जिसके चलते रोजगार बढ़ेगा एवं उद्योगों का विकास होगा।

हम सुधार मात्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, सुधार अच्छा तो है पर यह मौजूदा व्यवस्था को थोड़ा और बेहतर बनाने का ही काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना आमूल-चूल बदलाव का है। ऊपर वर्णित सभी योजनायें एवं कार्यक्रम बुनियादी तौर पर बदलाव लाने एवं आधारभूत संरचना को सही दिशा में उन्मुख करने की ओर लक्षित है। हमारी सरकार का अंतिम लक्ष्य ईमानदारी, अनुशासन, समर्पण एवं देशभक्ति की एक नयी संस्कृति का निर्माण है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री के आगे बढ़कर के नेतृत्व करने के सतत प्रयासों का अभिनन्दन करती है, जिनका लक्ष्य एक ऐसी कार्य संस्कृति का निर्माण है जहां ईमानदारी का सम्मान होता है और उसे उचित पारितोषिक मिलता है, जबकि बेईमानों को सुधार का रास्ता दिखाया जाता है।

हाल ही में ख़त्म हुए वर्ष में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने दुनिया के दस सबसे लोकप्रिय नेताओं ने उनका नाम शामिल किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह स्पष्टतापूर्वक स्वीकार करती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता को जनता ने उनके परिवर्तनकारी नीतियों एवं कार्यक्रम के कारण उनकी स्वीकारता को अतुलनीय लोकप्रियता के साथ स्वीकार किया है।

चुनावी जीत

वर्ष 2016 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दल के रूप में भी बहुत सफल वर्ष रहा है। चुनावी क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर में अपने सहयोगियों के साथ असम विधानसभा चुनाव दो तिहाई बहुमत के साथ जीतकर एक जोरदार प्रवेश किया है। वर्ष का अंत सुखद रहा जब अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत 33 विधायकों ने पीपीए छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का निर्णय किया। पार्टी पूर्वोत्तर में नए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता है। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दसवां और भाजपा गठबंधन द्वारा शासित चौदहवां प्रदेश बन गया।

भारतीय जनता पार्टी ने असम, मध्यप्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हुए लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों में आसन जीत दर्ज की है। वाम प्रभुत्व त्रिपुरा में, जहां यह धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए वाममोर्चा के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है, इसको नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। बंगाल में पार्टी ने सत्ताधारी दल की वीभत्स राजनीति के खिलाफ पार्टी ने संघर्ष करके उपचुनाव में भी विकल्प के रूप में द्वितीय स्थान पर रहकर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया।

पार्टी ने महाराष्ट्र, छतीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में जबरदस्त जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ निगम निगम चुनावों में हुई भारी जीत को विशेष रूप से उल्लेखित करने की जरुरत है, जहां पार्टी ने 26 सीटों में से 21 सीट जीतकर विपक्ष का लगभग सफाया कर दिया है।

पार्टी ने महाराष्ट्र, छतीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में जबरदस्त जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ निगम निगम चुनावों में हुई भारी जीत को विशेष रूप से उल्लेखित करने की जरुरत है, जहां पार्टी ने 26 सीटों में से 21 सीट जीतकर विपक्ष का लगभग सफाया कर दिया है। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि इनमें से अधिकतर चुनाव प्रधानमंत्री जी विमुद्रीकरण योजना के बाद हुए है। यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगा कि ये परिणाम विमुद्रीकरण कार्यक्रम के अपार समर्थन के प्रमाण हैं।

पार्टी ने अधिकतर राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को समापन कर दिया है और दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी समारोह के बैनर तले अधिकतर लोगों तक पहुचने की तैयारी कर रहा है

जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी विपक्ष

राष्ट्रीय कार्यकारिणी विपक्षी पार्टियों के द्वारा किये जा रहे जनविरोधी और लोकतंत्रविरोधी किये जा रहे कार्य की कड़ी निंदा करती है। वहीं शीतकालीन सत्र को कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों के सांसदों के द्वारा संसद सत्र न चलने देना संसदीय लोकतंत्र के साथ एक धोखा है।

आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी जैसी की तानाशाही रवैये वाली जनविरोधी सरकार के कारण राजनैतिक गतिविधि काफी कठिन

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन राज्यों में हो रहे सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा में प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करती है और राज्य सरकार के द्वारा लोकतंत्र विरोधी कार्य एवं उनके कुशासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को अवगत कराते रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मानना है कि मीडिया एवं बुद्धिजीवियों को राज्य द्वारा लोगों को तानाशाही शासन द्वारा प्रताड़ित करने पर एवं उनके अधिकार छिनने पर चुप नहीं रहना चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि उनके अपने साथियों को भी अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह प्रस्ताव पारित करती है कि तथाकथित मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों के झंडाबरदारों को इस मामले में उनकी चुप्पी इस हिंसा को समर्थन ही देती है।

हो गयी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बंगाल और केरल में लगातार हमले बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारों के द्वारा इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त किया है। इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा और अपराधियों को गुप्त रूप से मुक्त करने किया जाना सरकारी तंत्र के सहयोग के बिना असंभव है और यहां की राज्य सरकारें सरकारी तंत्र का जोर-शोर से दुरूपयोग कर रही है। वहीं बंगाल में धौलागढ़ का दंगा तृणमूल सरकार की नाकामियों को दर्शाता है जहां दंगाई एक तरफ तो लोगों के घर में जाकर उन्हें डराते और धमकाते हैं, वहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं तो दूसरी तरफ वहां की प्रशासन और पुलिस उस घटना को दूसरे तरह से प्रस्तुत करती है। यह अत्यंत दुखद घटना है कि नौकरशाही एवं कानून व्यवस्था का तंत्र इस परिस्थिति के सामने मूकदर्शक बन गए, जबकि कानून व्यवस्था की असफलता एवं अपराधियों का उत्पात होता रहा।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है कि पार्टी के विचार प्रणेता पंडित दीनदयाल जी के विचारों एवं सन्देश को प्रचारित करके स्वच्छ नागरिक जीवन एवं अन्त्योदय के विषयों को जनता तक लेकर जाएं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन राज्यों में हो रहे सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा में प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करती है और राज्य सरकार के द्वारा लोकतंत्र विरोधी कार्य एवं उनके कुशासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को अवगत कराते रहेगी।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मानना है कि मीडिया एवं बुद्धिजीवियों को राज्य द्वारा लोगों को तानाशाही शासन द्वारा प्रताड़ित करने पर एवं उनके अधिकार छिनने पर चुप नहीं रहना चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि उनके अपने साथियों को भी अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह प्रस्ताव पारित करती है कि तथाकथित मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों के झंडाबरदारों को इस मामले में उनकी चुप्पी इस हिंसा को समर्थन ही देती है।

इतिहास में अनेक दशकों तक भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के राजनीतिक हिंसा का अनेक बार सामना किया है और पार्टी इसको लोकतान्त्रिक तरीके से प्रतिरोध करना भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी यह संकल्प करती है कि लोकतान्त्रिक तरीके से बंगाल एवं केरल के सरकारों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया जायेगा।

चुनाव सुधार

राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के परिवर्तनकारी सुझाव का समर्थन कराती है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के चुनाव को एक साथ कराकर चुनाव सुधार को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह मानना है कि इस सुधार के साथ अन्य महत्वपूर्ण सुधारों को भी साथ लेकर देश में स्वस्थ चुनाव नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री जी के इस आवाहन पर देश की सभी राजनैतिक दलों, बुद्धजीवियों एवं मतदाताओं को संवाद करने का आवाहन करती है।

पंडित दीनदयाल जन्मशताब्दी एवं अन्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है कि पार्टी के विचार प्रणेता पंडित दीनदयाल जी के विचारों एवं सन्देश को प्रचारित करके स्वच्छ नागरिक जीवन एवं अन्त्योदय के विषयों को जनता तक लेकर जाएं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करती है कि इसके साथ श्री गुरुगोविंद सिंह जी के 350 वें प्रकाश उत्सव तथा नानाजी देशमुख जन्मशती कार्यक्रम में भी सहभागी हों। ■

एक साहसिक कदम- गरीब कल्याण की ओर

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 6 एवं 7 जनवरी 2017 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय वित मंत्री श्री अरुण जेटली ने आर्थिक प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन केंद्रीय खनन, इस्पात, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार का अभिनन्दन करती है कि सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण के इस निर्णय को पूरी तैयारी एवं जनविश्वास की कसौटी पर खरा उतरा है। यही कारण है कि केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहला निर्णय जहां कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का निर्णय लिया, वही स्वैच्छिक आयकर योजना, जनधन योजना, ब्लैकमनी एक्ट, बेनामी सम्पति एक्ट जैसे कानूनों को पास करके कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यवस्थागत एवं क़ानूनी प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए कदम उठाए गए है। हम यहां प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं...

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण द्वारा ग़रीब कल्याण हेतु लिए गए साहसिक निर्णय का स्वागत करती है। सरकार के इस दृढ़ निर्णय तथा उसकी विश्वसनीयता के साथ सफल क्रियान्वयन के लिए पार्टी, सरकार का हार्दिक अभिनंदन करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारत के 125 करोड़ जनमानस की ताकत को नमन करती है कि उन्होंने धैर्य और विश्वास के साथ सरकार के कालेधन के ख़िलाफ़ ग़रीबों के हित में साहसिक निर्णय का पूर्ण समर्थन किया है। इस वातावरण से देश में कालेधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली नोट, एवं काली कमाई के द्वारा निर्मित समानांतर अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक महत्वपूर्ण एवं सफल अभियान को जनमानस के सहयोग से सरकार ने पूर्ण किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अभिमत है कि यह लड़ाई सशक्त, समरस और समर्थवान भारत के पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सरकार के इस कदम से इस विश्वास को बल मिला है कि भारत की राजनीतिक परंपरा में अब केवल मात्र देशहित की बात करना देशभक्ति नहीं है, अपितु देशहित के लिए राजनीति से ऊपर उठकर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लेकर दृढ़ता एवं विश्वसनीयता के साथ कार्य करना देशभक्ति है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारत के 125 करोड़ जनमानस की ताकत को नमन करती है कि उन्होंने धैर्य और विश्वास के साथ सरकार के कालेधन के ख़िलाफ़ ग़रीबों के हित में साहसिक निर्णय का पूर्ण समर्थन किया है। इस वातावरण से देश में कालेधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली नोट, एवं काली कमाई के द्वारा निर्मित समानांतर अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक महत्वपूर्ण एवं सफल अभियान को जनमानस के सहयोग से सरकार ने पूर्ण किया है।

देशहित का यह कार्य भारत के गरीबों के आर्थिक समायोजन, पारदर्शी शासन एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बड़ा पड़ाव है। विमुद्रीकरण की यह प्रक्रिया कर नहीं देने वालों के काले धन का ग़रीबों और कमज़ोरों में वितरण होना है। देश के ईमानदार नागरिकों को सम्यक आजीविका, एक मज़बूत अर्थव्यवस्था एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार को बधाई देती है।

नकारात्मक राजनीति

इस पवित्र अभियान में एक ओर देश का जनमानस जहां उत्साह एवं

केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहला निर्णय जहां कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का निर्णय लिया, वही स्वैच्छिक आयकर योजना, जनधन योजना, ब्लैकमनी एक्ट, bankruptcy insolvency लॉ, डीआरटी संसोधित लॉ, बेनामी सम्पति एक्ट जैसे कानूनों को पास करके कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यवस्थागत एवं क़ानूनी प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए कदम उठाए गए है। आधार कानून के द्वारा गरीबों को उनका हक़ देने की सुनिश्चितता सरकार द्वारा की गयी है। देश में जीएसटी कानून के भविष्य में कुशल उपयोग के लिए, कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण आवश्यक था। आज देश में बैंकों के पास ऋण देने के लिए पहले से ज्यादा पैसा है और ब्याज दरें नीचे गिर रही हैं। अब अनौपचारिक और औपचारिक, दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठीक तरीक़े से आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे राज्यों और केंद्र को अधिक आय होगी और हम एक साफ़ और बढ़ी हुईं GDP की तरफ़ बढ़ेंगे।

सकारात्मक ऊर्जा के साथ, देश को लम्बे कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए थोड़ी तकलीफ सहकर भी पुनर्निमाण के संकल्प के लिए खड़ा रहा था। वही कई विपक्षी दलों के नकारात्मक प्रचार के द्वारा माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इस दिग्भ्रमित विपक्ष ने देश की संसद को चलने नहीं देकर जहां लोकतंत्र की मर्यादा के मानदंड को तोड़ा है, वहीं मुद्दों से भटकाने की भी पूरी कोशिश की परन्तु उनकी सब कोशिश असफल हुई हैं । लोगों ने सरकार की क्षमता पर भरोसा और विश्वास कर अपना पूर्ण समर्थन सरकार के निर्णय को दिया है। इसी का परिणाम है कि विमुद्रीकरण के 50 दिन के दौर में न तो आमजन का धैर्य टूटा,न ही बाजार में आपूर्ति में बाधा आई और न ही सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार की क्षति हुई। देश में रबी की बुवाई भी पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज्यादा हुई है।

देश में 107 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फ़ोन है, 147 करोड़ बैंक अकाउंट में से 117 करोड़ सेविंग अकाउंट एवं 25 करोड़ जनधन अकाउंट है। 35 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफ़ोन, 40 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर से खातों का जुड़ाव एवं 75 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड भारत की डिजिटल कारोबारी व्यवस्था के विकास हेतु एक सक्षम प्लेटफार्म है।

कालेधन के खिलाफ सुशासन के बढ़ते कदम

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार का अभिनन्दन करती है कि सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण के इस निर्णय को पूरी तैयारी एवं जनविश्वास की कसौटी पर खरा उतरा है। यही कारण है कि केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहला निर्णय जहां कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का निर्णय लिया, वही स्वैच्छिक आयकर योजना, जनधन योजना, ब्लैकमनी एक्ट, bankruptcy insolvency लॉ, डीआरटी संसोधित लॉ, बेनामी सम्पति एक्ट जैसे कानूनों को पास करके कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यवस्थागत एवं क़ानूनी प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए कदम उठाए गए है। आधार कानून के द्वारा गरीबों को उनका हक़ देने की सुनिश्चितता सरकार द्वारा की गयी है। देश में जीएसटी कानून के भविष्य में कुशल उपयोग के लिए, कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण आवश्यक था। आज देश में बैंकों के पास ऋण देने के लिए पहले से ज्यादा पैसा है और ब्याज दरें नीचे गिर रही हैं। अब अनौपचारिक और औपचारिक, दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठीक तरीक़े से आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे राज्यों और केंद्र को अधिक आय होगी और हम एक साफ़ और बढ़ी हुईं GDP की तरफ़ बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मानना है कि देश में 107 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फ़ोन है, 147 करोड़ बैंक अकाउंट में से 117 करोड़ सेविंग अकाउंट एवं 25 करोड़ जनधन अकाउंट है। 35 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफ़ोन, 40 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर से खातों का जुड़ाव एवं 75 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड भारत की डिजिटल कारोबारी व्यवस्था के विकास हेतु एक सक्षम प्लेटफार्म है। केंद्र सरकार द्वारा

कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस एवं रुपे-कार्ड के प्रयोग को बढ़ाना स्वागत योग्य है। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था नई भारत की ताकत

देश में मनरेगा, निर्धन छात्रों को छात्रवृति, वंचित वर्गों को सब्सिडी, एससी/एसटी एवं ओबीसी को दिए जाने वाली लाभकारी योजना में सरकार द्वारा डिजिटल प्रयोग से गरीबों के लाभ में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए संतोष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से जहां एक ओर देश में करों की चोरी को रोका जायेगा, वहीं औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस का भुगतान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, संविदा मजदूर अधिनियम तथा इस प्रकार के अन्य कानूनों से गरीबों के हित में अनुपालना हो सकेगी।

सरकार के द्वारा वर्तमान में जो वेतन अधिनियम का संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, वह देश के मजदूरों एवं कर्मचारियों के हित में सही समय पर लिया जाने वाला व्यवास्थानुकुल परिवर्तन है।

सरकार के डिजिटल व्यवस्था के इस कदम से जहां ईमानदार मध्यमवर्गीय करदाता, छोटा व्यापारी, छोटे कामगार, छोटे प्रोफेशनल जो अभी तक कालाबाजारी के आगे मूकदर्शक बने हुए थे, उन्हें सरकार के इस निर्णय से ताकत मिली है।

सरकार के डिजिटल व्यवस्था के इस कदम से जहां ईमानदार मध्यमवर्गीय करदाता, छोटा व्यापारी, छोटे कामगार, छोटे प्रोफेशनल जो अभी तक कालाबाजारी के आगे मूकदर्शक बने हुए थे, उन्हें सरकार के इस निर्णय से ताकत मिली है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस नववर्ष के प्रारंभ में देश के सर्वसमाज के लिए जो BHIM एप को समर्पित किया है, वह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संकल्पों को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का आश्वासन

8 नवम्बर को माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा से जहां देश में ईमानदारों के जीवन को सम्मान प्रदान किया, वहीं 31 दिसंबर की घोषणा ने किसान, छोटे व्यापारी, वरिष्ट नागरिक, व्यापारी, महिलाओं और युवाओं को एक नया विश्वास प्रदान किया है। 50 दिनों के पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा ढाई हज़ार रुपए से साढ़े चार हज़ार रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों और ग़रीबों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे स्वागतयोग्य हैं: 1) किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करने के लिए NABARD के कोश में 20,000 करोड़ रुपए, 2) रबी की फ़सल के लिए किसानों के 60 दिन का बिना ब्याज का ऋण, 3) तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रूपे डेबिट कार्ड, 4) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासों में 33% की वृद्धि, 5) दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को मुद्रा योजना में प्राथमिकता, 6) वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 साल की सावधि जमा पर 8 प्रतिशत ब्याज, 7) 12 लाख के गृह निर्माण ऋण पर ब्याज में छूट, 8) संस्थागत प्रसव पर 6000 रुपए की सहायता राशि सीधे प्रसूत के खाते में, 9) लघु और मध्यम उद्योगों के ऋणों की गारंटी 20 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत की।

राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च के बारे में प्रधानमंत्री जी का आवाहन परिवर्तनकारी है। भ्रष्टाचार और कालेधन से राजनैतिक दलों की मुक्ति भविष्य के भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत करती है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ कराने के लिए देश में एक राजनैतिक सर्वानुमति का वातावरण खड़ा किया जाये।

बदलेगा भारत बढ़ेगा भारत

भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना आवश्यक है। केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के इस कदम से सरकारी व्यवस्था के बाहर तहखानों में कैद पैसा वापस बैंक में आया है। सरकार के द्वारा चलाये गए इस अभियान में जिस दृढ़ता से सरकार द्वारा दोहरी चालाकियों एवं भ्रष्ट लोगों से लड़ाई लड़ी है, पार्टी उसका स्वागत करती है। देश के विकास का लाभ देश में हर नागरिक तक पहुंचे इसके लिए ईमानदार तरीके से देश में व्यापार का वातावरण बनाना आवश्यक है। पार्टी का यह मानना है कि विमुद्रीकरण और डिजिटल अर्थव्यवथा पर उसकी नीतियों एवं उनके कुशल क्रियान्वयन से हम विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करेंगे।

यह वर्ष 2017 पार्टी के विचार प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मशताब्दी वर्ष है और एकात्ममानववाद की विचारधारा के अनुरूप गरीबों के हितकारी एवं समतामूलक समाज के लिए सरकार के इस निर्णय का पार्टी स्वागत करती है। पार्टी का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लिए गए दृढ़ निर्णय एवं विश्वसनीय सरकार के प्रति जनता के विश्वास के भाव को धन्यवाद के लिए एक अभियान के माध्यम से संवाद करना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी, पारदर्शी शासन एवं कुशल नेतृत्व तथा जनता से संवाद के सेतु के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारों को समाज के सभी वर्गों तक ले जाना चाहिए। समाज में सबके लिए, सबके हित में निर्णय लेने का भाव रहे यही एकात्ममानववाद है।

सरकार के इस कदम से हम उस आधुनिक भारत को बनाने में सफल सिद्ध होंगे, जहां आधुनिक तकनीक, पारदर्शी शासन, सर्वजन हित, समरस समाज और सम्यक आजीविका के बेहतर तालमेल से हम 'सबका साथ-सबका विकास' के लक्ष्य को पूरा करेंगे। ■

गरीबी से लड़ना है, तो गरीब को ताकतवर बनाना होगा : नरेंद्र मोदी

संगठन के लोगों को हर वक्त तलवार की धार पर चलना होता है। संगठन में काम करने वालों पर दोहरा दवाब होता है। हमें यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में नीचे से ऊपर तक उत्तम तरीके से उत्तम संतुलन के साथ अच्छे तरीके से पार्टी की गतिविधियों को चलाया जा रहा है। सरकार में बैठे लोगों को इस बेहतर तालमेल की बदौलत चिंता की कोई जरूरत नहीं करनी पड़ती। इसका मूल कारण यह है कि शासन व्यवस्था और संगठन व्यवस्था के बीच जीवंत तालमेल और जीवंत अनुबंधन है।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले दो दिनों से देश और दल के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा जन-मन का प्रतिबिम्ब है क्योंकि हम वे लोग हैं जो धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और इसके कारण हमारे पास जमीनी सच्चाई को परखने की ताकत है। हम वो नहीं जो हवा के रुख में बह जाएँ, हम वो हैं जो हवा का रुख भांपकर, समझकर उसे मोड़ना जानते हैं।

जो शासन में बैठे हैं, उनके लिए भी यह मंथन, मार्गदर्शक का काम करता है। यह चिंतन, मनन और सुझाव हमारे लिए काफी मायने रखती हैं। इस संदर्भ में यह मेरे लिए और मेरे जैसे तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी द्वारा दिए गए दायित्त्व को निर्वहन करने का संबल है, विचारों का सम्पुट है।

जब हम शासन में नहीं होते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो दल की गतिविधि को चलाना अपेक्षाकृत सरल होता है लेकिन जब हम शासन में होते हैं तो ऐसे समय में संगठन को गति देना काफी कठिन होता है।

संगठन के लोगों को हर वक्त तलवार की धार पर चलना होता है। संगठन में काम करने वालों पर दोहरा दवाब होता है। हमें यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में नीचे से ऊपर तक उत्तम तरीके से उत्तम संतुलन के साथ अच्छे तरीके से पार्टी की गतिविधियों को चलाया जा रहा है। सरकार में बैठे लोगों को इस बेहतर तालमेल की बदौलत चिंता की कोई जरूरत नहीं करनी पड़ती। इसका मूल कारण यह है कि शासन व्यवस्था और संगठन व्यवस्था के बीच जीवंत तालमेल और जीवंत अनुबंधन है।

काले-धन की समस्या है, हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसको जीतेंगे भी। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन समाज की ऐसी शक्ति का दर्शन शायद ही किसी को देखने का सौभाग्य कभी प्राप्त होता है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। राष्ट्र पर बाहरी शक्तियों के आक्रमण के वक्त लड़ने के लिए देश इकट्ठा हो जाए, यह सहज व स्वाभाविक है लेकिन इस तरह के फैसले को जब देश की जनता-जनार्दन का इतना अभूतपूर्व समर्थन मिलता है तब बात ही कुछ और होती है - कुछ तो बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब भी हमारे अंदर बुराई आती है, हम खुद ही इससे लड़ने को खड़े हो जाते हैं। अस्पृश्यता, बाल-विवाह, अशिक्षा - इन सभी बुराइयों से लड़ने हम खुद ही तो खड़े हुए। यह घटनाक्रम उसी तारीख का हिस्सा है कि किस तरह अपने अंदर की बुराई से लड़ने के लिए हमने अपने अंदर सिंचित सच्चाई और अच्छाई की ऊर्जा का उपयोग किया और विजय श्री हासिल की।

बेनामी संपत्ति की शुरुआत भी कहीं-न-कहीं कैश करेंसी से ही होती है। जब तक हम इसकी मूल धारा को रोकने की व्यवस्था नहीं करते, हम काले-धन को व्यवस्था से बाहर नहीं कर सकते।

भारत ने देश की 86% चलन की मुद्रा को ख़त्म करके जो दिखाया है, यह निर्णय की सफलता नहीं, बल्कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की समझदारी की सफलता है। हमने जितनी चलन की करेंसी अर्थव्यवस्था से ख़त्म की है, वह विश्व के लगभग 60-70% देशों की टोटल करेंसी के बराबर है।

जब देश के गरीब-से-गरीब लोगों को लगता है कि यही रास्ता है जो शायद हमें बचाएगा, हमें सशक्त बनाने में सहायक होगा, तब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है।

आखिर क्या कारण है कि छतीसगढ़ की 90 साल की एक बुजुर्ग महिला अपनी बकरी बेचकर गाँव का पहला टॉयलेट बनवाती है और लोगों को खुले में शौच के लिए न जाने की प्रेरणा देती है। इसका मतलब यह है कि हमारी सारी योजनायें जन-सामान्य से जुड़ी हुई है।

अन्य राजनीतिक दलों के लिए गरीबी चुनाव मे भुनाने का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यह हमारे लिए गरीबों का उत्थान, उनकी सेवा का अवसर है। गरीब हमारे लिए मदद नहीं, सेवा का क्षेत्र है। हमारी विधि, वाणी, निर्णय और प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में गरीब नहीं रहेगा तो हम अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पायेंगे।

हमारे देश में दो प्रकार की सामाजिक स्थिति है। एक तरफ वो वर्ग है जिसके लिए लाइफ स्टाइल की अहमियत बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ, एक बहुत बड़ा तबका है जो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ के लिए जूझ रहा है। हमारे सामने दो रास्ते हैं। हमने लाइफ स्टाइल नहीं, क्वालिटी ऑफ़ लाइफ में परिवर्तन लाने का रास्ता चुना है। हमारी पूरी सोच का दायरा समर्पण और कर्त्तव्य भाव से इसे पूरा करने का संकल्प होना चाहिए।

> गरीबी से लड़ना है तो गरीब को ताकतवर बनाना होगा। गरीबी को परास्त करने की ताकत देश के गरीबों में ही है, जरूरत इस बात की है कि उन्हें अवसर दिए जाएँ।

भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें 'भारत माता की जय' के सिवा कुछ और नहीं चाहिए।

वाराणसी में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठकर चपाती खाने का अनुभव मेरे लिए चिर-स्मरणीय रहेगा। यह मेरे जीवन का अभूतपूर्व क्षण था।

निर्णय तो पहले की सरकारें भी लिया करती थीं लेकिन उसकी कभी मॉनिटरिंग सही से नहीं होती थी। फैसले फाइलों की धूल फांकते रहते थे। हमारी सरकार हर निर्णय का हर दिन हिसाब लेती है।

क्या हमें इस बात के लिए पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18000 गाँव अँधेरे में जीवनयापन करने को मजबूर थे?

गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए सोलर लाइट देने की व्यवस्था की जा रही है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना क्या है - यह सब गरीबों के उत्थान की ही योजनायें हैं। सबसे ज्यादा अशिक्षा माइनॉरिटीज वर्ग में है, गरीब वर्ग में है, हम वहां की व्यवस्था बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन को सुधारा जा सके।

हम गरीबों के लिए सरकार की योजनाओं को चिह्नित करें और इसे लोगों तक ले जाए, उन्हें इसकी जानकारी दें और इससे लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।

गरीबी से लड़ना है तो गरीब को ताकतवर बनाना होगा। गरीबी को परास्त करने की ताकत देश के गरीबों में ही है, जरूरत इस बात की है कि उन्हें अवसर दिए जाएँ। यदि हमारी सारी योजनाओं के मूल में इस बात पर बल दिया जाय, तो हम निश्चित रूप से देश से गरीबी को ख़त्म करने में सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।

मैं इस अवसर पर राजा रंतिदेव का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था - न मुझे राज्य की कामना है, न ही मोक्ष अथवा ऐश्वर्य की, मुझे तो गरीबों के आंसू पोंछने की कामना है। हम उस शासन व्यवस्था के लोग हैं। इतिहास ऐसे मौके कभी किसी को नहीं देता जैसा मौक़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है।

देश बदलने को तैयार है, हम ही कहीं न पीछे रह जाएँ।

डिजिटल इंडिया का नोटबंदी से कोई लेना-देना नहीं है। डिजिटल इंडिया की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। ई-गवर्नेंस का आज के समय में कितना महत्त्व है, यह समझने की जरूरत है। डिजिटाईजेशन अब हमारे सामाजिक जीवन की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ता इस अभियान को अपना मानकर चल पड़ें, तो हम इसके बल पर देश की इकॉनमी को बदल सकते हैं।

आने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के जो दृश्य उभर कर सामने आ रहे हैं, यह काफी हौसला बढ़ाने वाला है। यदि हवा का रुख हमारे लिए अनुकूल है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए।

सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता आने वाली है। राजनीतिक दलों को चंदे के लिए पारदर्शी रास्ते अपनाने ही पड़ेंगे। हमें इस अभियान को आगे बढ़ कर लीड करना चाहिए। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देश के करोड़ों-करोड़ जनता-जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम देश की राजनीति में पारदर्शी व्यवस्था के पक्ष में हैं। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

हम एक विशिष्ट जिम्मेदारी निभाने वाले दल हैं। मैं गरीबी में जन्मा, गरीबी में जिया। मैं गरीबी के दर्द को समझता हूँ। देश में करोड़ों गरीब लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। हमने उनकी भलाई की राह पर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। देश में करोड़ों गरीब लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। हमने उनकी भलाई की राह पर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए और आरोपों से घबराना नहीं चाहिए। हम सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलें और देश के पुनर्निर्माण में सहायक बनें।

पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ■

पूरा प्रदेश परिवर्तन का मन बना चुका है: नरेंद्र मोदी

2 जनवरी को लखनऊ स्थित रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि इतिहास रच गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस महारैली में लाखों लोग उमड़ पड़े और इसने अब तक की सभी पार्टियों द्वारा आयोजित रैली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। भारी भीड़ से उत्साहित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में कई रैलियों को संबोधित करने का अवसर मिला है, पर इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का सौभाग्य नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा विशाल दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि लखनऊ की जनसभा में उमड़े जनसैलाब से यह साफ है कि जनता भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के समर्थन को देखते हुए यह तय लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 14 साल से विकास का जो वनवास चल रहा है वह खत्म होने वाला है। पूरा प्रदेश परिवर्तन का मन बना चुका है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह अटल जी की कर्मभूमि है। आज का दृश्य जब वो टीवी पर देख रहे होंगे तो बेहद खुश होंगे। राजनीतिक पंडित भी इस रैली को देखकर नतीजों को आसानी से समझ गए होंगे। आज के समय में जब छह महीने में लोग पुरानी सरकार को भूल जाते हैं, लेकिन 14 साल पहले के कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और रामप्रकाश जी के शासन को लोग याद करते हैं और वर्तमान सरकार से उसकी तुलना भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में 14 साल से विकास का वनवास चल रहा है। विकास का नया अवसर अब आने वाला है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आपने मुझे सांसद बनाया और सरकार बनाने में भी बड़ा योगदान दिया। केंद्र सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान से गरीबी, निरक्षरता और बीमारी मिटे। जब तक उत्तर प्रदेश से यह दूर नहीं होगा और इसका विकास नहीं होगा। देश का भाग्य नहीं बदल सकता। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की कि जात-पांत और अपने पराए से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विरोध के चलते विकास नहीं होने दिया जा रहा। जनता परेशान होती है। सांसदों की शिकायत है कि राज्य सरकार सुनती नहीं है। ढाई साल में ढाई लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं। केंद्र सरकार के पैसों से ही राज्य की कायापलट हो सकती थी।

किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों तक गन्ना किसानों का पैसा लटका रहा। केंद्र ने ज्यादातर पैसा चुकता किया। उत्तर प्रदेश में विकास के आड़े अपने पराए का भाव और राजनीति आ रही है जिसके चलते जनता पिछड़ रही है। किसान इतनी मेहनत करता है। बाजार में धान आया, लेकिन भारत सरकार से एमएसपी तय करने और पूरी मदद के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार

भाजपा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप विकसित करेगी: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 जनवरी को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्टेडियम में परिवर्तन महारैली को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा बस आरोपों की राजनीति ही करते आए हैं। संसाधनों की भरमार के बावजूद राज्य का विकास नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ही राज्य को उत्तम प्रदेश बना सकती है। देश की तकदीर बनाने वाले राज्य के युवा में अपने प्रदेश को न बदल पाने की छटपटाहट है इसलिए परिवर्तन तय है।

श्री शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन शब्द का प्रयोग सरकार, मुख्यमंत्री या विधायक बदलने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलने के लिए किया गया है। पंद्रह साल से प्रदेश में चाचा-भतीजा और बुआ भतीजा की सरकार ने राज्य को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। ये राज्य का भला नहीं कर सकते। प्रदेश के विकास के लिए श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लानी होगी। हम सिर्फ वादे नहीं करते बीजेपी शासित राज्यों ने विकास करके दिखाया है। देश के 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में आजादी के इतने साल बाद भी हर घर में बिजली, स्कूलों में शिक्षक और शिक्षकों को कमरे नसीब नही हुए हैं। भ्रष्टाचार के चलते रोजगार, स्वास्थ्य, सस्ती दवाएं, सड़कों से जुड़ाव भी नहीं हो पाया है। मंडी में किसानों को उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल में ज्यादातर राज्य में कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारें रहीं, लेकिन गांव में झोपड़ी

से धुंआ हटाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ढाई साल में डेढ़ करोड़ गैस कनेक्शन, बीस करोड़ बैंक खाते, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया जैसे उपहार जनता को दिए। चाचा भतीजा के कमीशन को लेकर चले झगड़े में फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही नहीं भरा गया। इसलिए उत्तर प्रदेश को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार नब्बे से ज्यादा योजनाएं गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए लाई है।

श्री शाह ने आह्वान किया कि अखिलेश सरकार को उखाड़ फेंकिए और राज्य में विकास का मार्ग प्रशस्त कीजिए। ■

को खरीद की फुर्सत नहीं है। दाल की पैदावार अच्छी होने के बावजूद राज्य सरकार नहीं खरीद रही।

श्री मोदी ने कहा कि सपा और बसपा हमेशा विपरीत दिशा में चले, लेकिन कालेधन पर कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दोनों दल मिलकर कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। वो कह रहे हैं मोदी को हटाओ मैं कहता हूं कालेधन और भ्रष्टाचार को हटाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने भीम एप लांच किया गया। आर्थिक चिंतक और रिजर्व बैंक के प्रणेता डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एप शुरू करने का भी विरोध किया गया। गांव गांव जाकर लोगों को इसका इस्तेमाल करना सिखाना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में चुनाव लड़ने वाले दलों में कुछ ऐसे हैं, जिनका अता पता ही नहीं। एक दल पंद्रह साल से बेटे को स्थापित करने में ही जुटा है। एक अन्य दल पैसा बचाने में लगा है, वहीं एक दल परिवार के झगड़े में उलझा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही राज्य की चिंता के साथ आगे आई है। केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत के कारण ही अच्छे फैसले ले पा रही है। केंद्र सरकार की हाईकमान सवा सौ करोड़ जनता है। अब राज्य की जनता को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आधा अधूरा नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था बेहतर होगी और गुंडाराज खत्म होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। गरीबों को उनका हक लौटाने और मध्यम वर्ग का शोषण रोकने के लिए कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी गई है। विरोधी दलों को नोटबंदी से भी परेशानी है और गरीबों के लिए योजनाओं की घोषणा में भी परेशानी है। विरोधवाद की राजनीति देश में अप्रासंगिक हो गई है। अन्य दलों के लिए उत्तर प्रदेश का यह चुनाव सत्ता का खेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव एक जिम्मेदारी है। हमें इस जिम्मेदारी के लिए योग्य बनाकर आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान को बदलने की नींव उत्तर प्रदेश में है। ■

'छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने लहराया परचम

विमुद्रीकरण के फैसले के बाद संपन्न हुए छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा स्थानीय निकाय के चुनावों में देश की जनता ने भाजपा को विजयश्री दिलाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फैसले पर मुहर लगाने का काम किया।

गुजरात

गुजरात में विगत 27 दिसंबर को संपन्न हुए 10212 ग्राम पंचायतों के चुनाव में अब तक घोषित परिणामों के अनुसार कुल 7363 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को केवल 2395 व अन्य को 454 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। यहां भाजपा की जीत का प्रतिशत 72% से अधिक है। भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने राज्य के सभी चार जोन में शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा को सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद के साथ-साथ राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर और कच्छ के इलाके में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में भी 27 दिसंबर को चरौदा नगर निगम (भिलाई) और सारंगढ़ नगरपालिका परिषद् के चुनाव हुए थे, यहां दोनों जगह भाजपा ने अच्छे अंतर से जीत दर्ज की। चरौदा नगर निगम से भाजपा के महापौर चुने गए हैं, साथ ही सारंगढ़ नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष पद भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया। डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की यह लगातार छठी जीत है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी को 244 सीटों में से 100 सीटें मिलीं। इसमें से भाजपा को सात स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पद पर भी जीत हासिल हुई। आखिरी चरण का परिणाम आने के बाद राज्य में सत्ता प्रतिष्ठान भाजपा के स्थानीय निकाय अध्यक्षों में 71 पद मिले। साथ ही 1,190 पद निगम पार्षदों के मिले। बता दें कि राज्य के नागपुर और गोंदिया जिले में 11 नगर निगम और नगर पंचायत के लिए आखिरी चरण का मतदान 8 जनवरी को हुआ था। जिन 11 नगर निगम और पंचायतों में मतदान हुआ था, उसमें. नागपुर के कमाठी, उमरेद, कतोल, कलमेश्वर, मोहपा, रामतेक, नारखेड, खापा और साओनेर तथा गोंदिया जिले के तिरोरा और गोंदिया शामिल हैं। 11 नगर निगमों में अध्यक्ष पद के लिए 92 उम्मीदवार थे। यही नहीं, इन दो जिलों में 244 पार्षद सीटों के लिए 1190 उम्मीदवार थे। जानकारी के मुताबिक संपन्न हुए आखिरी चरण में 67.36 फीसद मतदान हुआ था। बता दें कि इन चुनावों में कांग्रेस के खाते में 58 सीटें आई। 2 काउंसिल के अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस सफल रही। इस चुनाव में कांग्रेस 952 पार्षद और 34 काउंसिल अध्यक्ष पदों पर जीत हासिल कर दूसरे नंबर रही। इस चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 26 पार्षद सीटें जीतकर कुल 812 सीटें हासिल की। पार्टी के 22 उम्मीदवार काउंसिल अध्यक्ष पदों पर भी जीत हासिल की। हालांकि चौथे चरण में पार्टी के खाते में एक भी अध्यक्ष पद नहीं आया। बात शिवसेना की करें तो उसने 3 चरणों में 598 सीटें जीतीं। चौथे चरण में पार्टी ने 14 और सीटें जीतीं। दोनों मिलाकर 612 उम्मीदवार पार्षद पदों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे। शिवसेना ने 26 काउंसिल अध्यक्ष पदों पर भी अपनी जीत का परचम लहराया।

'भाजपा सरकारों की गरीब-कल्याण नीतियों की जीत'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा को मिल रहा लगातार अभूतपूर्व जनसमर्थन पार्टी की विकासोन्मुखी नीतियों एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत की जीत है। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाईजेशन के फैसले के बाद संपन्न हुए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा व फिर से गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता भ्रष्टाचार और काले-धन की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ है, जबकि विपक्ष डिमोनेटाईजेशन के फैसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है।

फरीदाबाद

फ़रीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय हुई। नगर निगम की 40 सीटों के लिए 8 जनवरी को संपन्न हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दो-तिहाई (30 सीट) सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 10 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। ■

होम लोन पर ब्याज में 4% तक छूट

किसानों, गरीबों और गर्भवती महिलाओं को भारी राहत

नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग को नए साल का शानदार तोहफा दिया। श्री मोदी ने कहा कि गांव-गरीब-किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और महिलाएं, जितनी सशक्त होंगी, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होंगी, देश उतना ही मजबूत बनेगा और विकास भी उतना ही तेज होगा।

8 नवंबर को विमुद्रीकरण पर ऐतिहासिक फैसले के बाद 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, गरीबों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के विकास हेतु कई प्रमुख निर्णय लिए। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी देश में लाखों गरीबों के पास अपना घर नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में कालाधन बढ़ा, तो मध्यम वर्ग की पहुंच से घर भी खरीदना दूर हो गया था। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं।

घर बनाने हेतु लिए गए कर्ज पर ब्याज में 4 प्रतिशत तक की छूट

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए दो नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानी जितने घर पहले बनने वाले थे, उससे 33 प्रतिशत ज्यादा घर बनाए जाएंगे।

गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है। 2017 में गांव के जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं, एक-दो कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3 प्रतिशत

गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए सस्ता मकान

- शहरों में: 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट।
- गांव में: जो लोग घर बनाना चाहते हैं या पुराने घर में एक-दो कमरे या मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें दो लाख रुपए तक के कर्ज में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे।

गर्भवती महिलाएं

- गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए छह हजार रुपए की मदद।
- देश के सभी 650 जिलों में सरकारी अस्पताल में जाने पर यह रकम गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधे जमा होगी।
- गौरतलब है कि इस समय सिर्फ चार हजार रुपए की मदद 53 जिलों में महिलाओं को दी जा रही है।

बुजुर्ग

- साढ़े सात लाख रुपए की रकम पर 10 साल के लिए सालाना 8% ब्याज मिलेगा।
- बुजुर्ग हर महीने ब्याज का पैसा ले सकेंगे।
- देश में 60 से ज्यादा उम्र के 10.40 करोड़ लोगों को फायदा।

छोटे कारोबारी

- क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए की जाएगी। बैंकों से कहा गया है कैश क्रेडिट लिमिट 20% से बढ़ाकर 25% करें और वर्किंग कैपिटल लोन 20% से बढ़ाकर 30% करें।
- अभी तक एक करोड़ रुपए तक का लोन कवर किया जाता था। अब दो करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। गारंटी का खर्च सरकार उठाएगी। इससे ब्याज दर कम होगा।

किसान

- डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने बुवाई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार भरेगी। तीन महीने में तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदला जाएगा।
- 60 दिन का ब्याज सरकार किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। रुपे कार्ड में बदलने से किसान कहीं पर भी खरीद-बिक्री कर पाएगा।

ब्याज की छूट दी जाएगी।

किसानों के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी

मोदी सरकार ने इस बात का लगातार ध्यान रखा है कि किसानों को बीज की दिक्कत ना हो, खाद की दिक्कत ना हो, कर्ज लेने में परेशानी ना आए। सरकार ने अब किसानों के हित में कुछ और अहम निर्णय लिए हैं।

डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी।

कोऑपरेटिव बैंक और सोसायटीज से किसानों को और ज्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए उपाय किए गए हैं। नाबार्ड ने पिछले महीने 21 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अब सरकार इसे लगभग दोगुना करते हुए इसमें 20 हजार करोड़ रुपए और जोड़ रही है। इस रकम को नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक और सोसायटीज को कम ब्याज पर देगा और इससे नाबार्ड को जो आर्थिक नुकसान होगा है, उसे भी सरकार वहन करेगी।

गौरतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष रबी की बुवाई 6 प्रतिशत ज्यादा हुई है। फर्टिलाइजर भी 9 प्रतिशत ज्यादा उठाया गया है।

सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले तीन महीने में 3 करोड़

सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले तीन महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रूपे कार्ड में बदला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदल दिया जाएगा, तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद-बिक्री कर पाएगा।

किसान क्रेडिट कार्डों को रूपे कार्ड में बदला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदल दिया जाएगा, तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद-बिक्री कर पाएगा।

छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ रुपए

देश में रोजगार वृद्धि के लिए लघु और मध्यम उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, जो रोजगार बढ़ाने में सहायक होंगे।

सरकार ने तय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करेगी। गौरतलब है कि भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को ये गारंटी देती है । अब तक यह नियम था कि एक करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था। अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी से दिया गया लोन भी इसमें कवर होगा।

सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदारों, छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलेगा। गारंटी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने के कारण इन पर ब्याज दर भी कम होगी।

सरकार ने बैंकों को ये भी कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करें। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से हुए ट्रांजेक्शन पर वर्किंग कैपिटल लोन 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक करने को कहा गया है। नवंबर में इस सेक्टर से जुड़े बहुत से लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। बैंकों को कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल तय करते वक्त इसका भी संज्ञान लें।

कुछ दिन पहले ही सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में बड़ी राहत देने का भी निश्चय किया था। जो कारोबारी साल में 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार करते हैं, उनके टैक्स की गणना 8 प्रतिशत आय को मानकर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारी के डिजिटल लेन देन पर टेक्स की गणना 6 प्रतिशत आय मानकर की जाएगी। इस तरह उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा।

मुद्रा योजना की सफलता निश्चित तौर पर बहुत उत्साहवर्धक रही है। पिछले साल करीब-करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दलित-आदिवासी-पिछड़ों, एवं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार का, इसे अब डबल करने का इरादा है।

गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए की मदद

> गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब देश के सभी, 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलिवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी।

गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब देश के सभी, 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलिवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने में इस योजना से बड़ी सहायता मिलेगी। वर्तमान में यह योजना 4 हजार की आर्थिक मदद के साथ देश के सिर्फ 53 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही थी।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक स्कीम शुरू करने जा रही है। बैंक में ज्यादा पैसा आने पर प्रायः बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दर घटा देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों पर इसका प्रभाव ना हो इसलिए 7.5 लाख रुपए तक की राशि पर 10 साल तक के लिए सालाना 8 प्रतिशत का ब्याज दर सुरक्षित किया जाएगा। ब्याज की यह राशि वरिष्ठ नागरिक हर महीने पा सकते हैं। ■

सिंगापुर के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि संशोधित

भारत और सिंगापुर ने 30 दिसंबर को संशोधित दोहरा कराधान बचाव संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सिंगापुर के रास्ते आने वाले निवेश पर भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री श्री अरुण जेतली ने इस संशोधित संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कहा कि देश का कालाधन सिंगापुर, मॉरिशस और साइप्रस के रास्ते आ रहा था। इन देशों के साथ अभी तक दोहरे कराधान समझौते (डीटीएए) के तहत सिंगापुर से होने वाले निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था। मोदी सरकार ने एक वर्ष के भीतर इन तीनों देशों के साथ दशकों पहले हुई संधियों को संशोधित कर देश के कालेधन को बाहर भेजकर फिर से निवेश के रूप में वापस लाने के खेल पर रोक लगाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि संशोधित संधि के तहत 31 मार्च 2017 तक होने वाले निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन, 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के दौरान होने वाले पूंजीगत लाभ पर 50 फीसदी कर लगेगा, जबकि 01 अप्रैल 2019 से घरेलू दर से पूर्ण पूंजीगत लाभ कर लगेगा। उन्होंने कहा कि कालेधन के विरुद्ध जारी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष नवंबर में स्विटजरलैंड के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान का करार किया गया है। इसके तहत वर्ष 2018 में स्विटजरलैंड में किसी भी तरह से किए जाने पर निवेश या जमा के बारे में वर्ष 2019 से जानकारी मिलने लगेगी।

गौरतलब है कि 2014-15 में देश में 24.7 अरब डॉलर एफडीआई आया था। इसमें से 24% मॉरीशस और 21% सिंगापुर के जरिए आया था। अप्रैल 2000 से सितंबर 2016 तक 49% एफडीआई मॉरीशस और सिंगापुर से आया। ■

जीवन का ध्येय

| दीनदयाल उपाध्याय |

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक विचारक थे। देशभर में उनकी जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) के अवसर पर संगोष्ठियों का आयोजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। कमल संदेश में भी हम लगातार उनके द्वारा लिखे गए विचारशील लेखों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार हम राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका 'पांचजन्य'(18 अगस्त, 1949) में प्रकाशित निम्न लेख यहां दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है अंतिम भाग-

हमारी स्वतंत्रता

ऐसी दशा में उस राष्ट्र के घटकों का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि विजेता राष्ट्र के प्रभुत्व को नष्ट करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्र किया जाए। उस राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति विदेशी राष्ट्र के प्रति विद्रोह की भावना लेकर खड़ी हो जाती है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवसर प्राप्त होने पर स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। विश्व के इस नियम के अनुसार भारतवर्ष ने भी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा किया और अंत में एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली।

15 अगस्त, 1947 को हमने एक मोरचा जीत लिया। हमारे देश से अंग्रेजी राज्य विदा हो गया। उस राज्य के कारण हमारी प्रतिभा के विकास में जो बाधाएं उपस्थित की जा रही थीं, उनका कारण हट गया, हम अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हो गए। अपनी आत्मानुभूति का मार्ग खुल गया। किंतु अभी भी मानव की प्रगति में हमको सहायता करनी है। मानव द्वारा छेड़े गए युद्ध में जिन-जिन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हमने अब तक किया है, जिनके चलाने में हम निपुण हैं तथा जिन पर पिछली सहस्राब्दियों में जंग लग गई थी उन्हें पुनः तीक्ष्ण करना है तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देकर मानव को विजय बनाना है। आज यदि हमारे मन में उन पद्धतियों के विषय में ही मोह पैदा हो जाए, जिनके पुरस्कर्ताओं से हम अब तक लड़ते रहे हैं, तो यही कहना होगा कि हम न तो स्वतंत्रता का सच्चा स्वरूप समझ पाए हैं और न अपने जीवन के ध्येय को ही पहचान पाए हैं। हमारी आत्मा ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह केवल इसलिए नहीं किया कि दिल्ली में बैठकर राज्य करने वाला एक अंग्रेज था, अपितु इसलिए भी कि हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन की गति में विदेशी पद्धतियां और रीति-रिवाज विदेशी दृष्टिकोण और आदर्श अडंगा लगा रहे थे, हमारे संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे थे, हमारे लिए सांस लेना भी दूभर हो गया था। आज यदि दिल्ली का शासनकर्ता अंग्रेज के स्थान पर हममें से ही एक, हमारे ही रक्त और मांस का एक अंश हो गया है तो हमको इसका हर्ष है, संतोष है; किंतु हम चाहते हैं कि उनकी भावनाएं और कामनाएं भी हमारी भावनाएं और कामनाएं हों। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रंजकण का इतिहास उसके शरीर के कण-कण से प्रति ध्वनित होना चाहिए; तीस कोटि के हृदयों को समष्टिगत भावनाओं से उसका हृदय उद्वेलित होना चाहिए तथा उनके जीवन के विकासक अनुकूल, उनकी प्रकृति और स्वभाव अनुसार तथा उनकी भावनाओं और कामनाओं के अनुरूप पद्धतियों की सृष्टि उसके द्वारा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमको कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी है। अभी हम अपनी आत्मानुभूति में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाए हैं।

> आर्थिक स्वाधीनता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्नों में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों की राष्ट्र अपनी सहायता के लिए सृष्टि करता है अथवा जिन रीति-रिवाजों में उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वे ही यदि कालावपात से उसके मार्ग में बाधक होकर उसके ऊपर भार रूप हो जाएं तो उनसे मुक्ति पाना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है।

सब प्रकार स्वतंत्र हों

अंग्रेजी राज्य के चले जाने के बाद आवश्यक है कि हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का अनुभव करें। जब तक भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से परमुखापेक्षी है तथा भारत को तीस कोटि संतान की आर्थिक उन्नति का समान अवसर प्राप्त नहीं है, जब तक उनकी उन्नति के द्वार खुले नहीं हैं तथा उसके साधन प्रस्तुत नहीं हैं, तब तक भारतवर्ष विश्व की प्रगति में कदापि सहायक नहीं हो सकता। न तो वह जीवन के सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा और न मानव की स्वतंत्रता का ही।

आर्थिक स्वाधीनता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्नों में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों की राष्ट्र अपनी सहायता के लिए सृष्टि करता है अथवा जिन रीति-रिवाजों में उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वे ही यदि कालावपात से उसके मार्ग में बाधक होकर उसके ऊपर भार रूप हो जाएं तो उनसे मुक्ति पाना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यात्रा की एक मंजिल में जो साधन उपयोगी

सिद्ध हुए हैं वे दूसरी मंजिल में भी उपयोगी सिद्ध होंगे यह आवश्यक नहीं। साधन तो प्रत्येक मंजिल के अनुरूप ही चाहिए तथा इस प्रकार प्रयाण करते हुए प्राचीन साधनों का मोह परतंत्रता का ही कारण हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल उन तंत्रों का समष्टिगत नाम है जो स्वानुभूति में सहायक होते हैं।

सांस्कृतिक स्वतंत्रता

राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यंत महत्त्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्त्वों पर विलय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती, अपितु वह निरंतर गतिशील फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है। नदी के प्रवाह की भांति निरंतर गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएं रखती हैं जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले समाज के संस्कारों में तथा उस सांस्कृतिक भावना से जन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति शास्त्र, समाज रचना इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग अंगों में व्यक्त होती हैं। परतंत्रता के काल में इन सब पर प्रभाव पड़ जाता है तथा स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। आज स्वतंत्र होने पर आवश्यक है कि हमारे प्रवाह की संपूर्ण बाधाएं दूर हों तथा हम अपनी प्रतिभा अनुरूप राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्रों में विकास कर सकें। राष्ट्र भक्ति की भावना को निर्माण करने और उसको साकार स्वरूप देने का श्रेय भी राष्ट्र की संस्कृति को ही है तथा वही राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मानव की एकात्मता का अनुभव कराती है। अतः संस्कृति की स्वतंत्रता परमावश्यक है। बिना उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता निरर्थक ही नहीं, टिकाऊ भी नहीं रह सकेगी।

राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यंत महत्त्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्त्वों पर विलय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है वह उसकी संस्कृति है।

स्वार्थ का साधन नहीं

आज अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उत्सव मनाते समय हम स्वतंत्रता के इन मूल्यों को समझें। स्वतंत्रता की कुछ व्यक्ति समूह के स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाना, फिर वह व्यक्ति समूह तीस करोड़ का ही क्यों न हो, स्वतंत्रता को उसके महान् आसन से गिराकर धूल में मिलाना होगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण से कार्य करने पर न तो स्वतंत्रता को हम अनुभूति ही कर पाएंगे और न हम विश्व को ही कुछ सेवा कर पाएंगे। अपितु इस प्रकार का स्वार्थी और अहंकारी भाव लेकर कार्य करने पर हम उसी इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे जो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव जमाने में निर्माण करता है। यहां पात्र भिन्न होंगे, वे एक ही राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव जमाने में निर्माण करता है। यहां पात्र भिन्न होंगे, वे एक ही राष्ट्र के घटक होंगे, पास-पास रहनेवाले पड़ोसी होंगे और इसलिए उनके कृत्य और भी भयंकर हो जाते हैं तथा उसका परिणाम भी सर्वव्यापी विनाश हो सकता है। किंतु हमारा विश्वास है कि राष्ट्र की जीवनदायिनी शक्ति अपने सच्चे स्वरूप और कार्य को समझेगी तथा विनाश के स्थान पर विकास के मार्ग पर अग्रसर होती हुई भारत की तीस कोटि संतान अपने परम लक्ष्य परब्रह्म की प्राप्ति तथा विश्वात्मा की अनुभूति कराएगी। ■

(समाप्त)

नहीं रहे सुंदरलाल पटवा

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा का 28 दिसंबर, 2016 को हृदयाघात के बाद निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे। उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है और उन्हें कोई संतान नहीं थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि सुंदर लाल पटवा जी का निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनहित और विकास कार्यों को समर्पित कर दिया था। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आजीवन प्रयासरत रहने वाले पटवा जी आप स्वच्छ राजनीति के पर्याय हैं, आपको भुलाया नहीं जा सकेगा।

श्री सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में पहली भाजपा सरकार में शामिल रहे। भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके श्री पटवा दो बार राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। पहले वह 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनाए गए।

श्री सुंदर लाल पटवा का जन्म 11 नवंबर 1924 को हुआ था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से की। 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंदोलन में भाग लेने के लिए श्री पटवा सात महीने जेल में रहे। गौरतलब है कि आपातकाल के दौरान श्री पटवा को मीसा के तहत हिरासत में भी लिया गया था। श्री पटवा ने 1997 में छिंदवाड़ा पहला लोकसभा उपचुनाव जीता। 1999 में वह होशंगाबाद लोकसभा सीट जीते और 1999 से 2001 तक वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। ■

@narendramodi

श्री सुंदर लाल पटवा के निधन पर दुःख हुआ। वह बहुत ही मेहनती और समर्पित नेता थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को याद किया जाएगा।

@AmitShah

पटवा जी ने जनसंघ से लेकर भाजपा तक कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका कठोर परिश्रम और समर्पण कार्यकर्ताओं को निरन्तर प्रेरणा देता रहेगा।

'वे मूल्याधारित राजनीति के प्रखर प्रवक्ता थे'

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदर लाल पटवा के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने शोक संदेश में कहा कि मुझे जानकार यह अत्यंत दुःख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुंदर लाल पटवा जी का निधन हो गया। वे एक समर्पित स्वयंसेवक, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता एवं उत्कृष्ट राजनेता थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री पटवा मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे, लोक सभा सांसद रहे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे। मूल्य आधारित राजनीति के प्रखर प्रवक्ता रहे पटवा जी जनता की मुखर आवाज थे, आपातकाल के दौरान मीसा बंदी के रूप में वे जेल में भी रहे।

सौम्य व्यक्तित्त्व, कुशल सांगठनिक क्षमता, ओजस्वी वक्ता और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक जुझारू नेता के रूप में श्री सुंदर लाल पटवा सदैव याद किये जायेंगे। उनके निधन से देश ने राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता एवं कुशल मार्गदर्शक को खो दिया है। श्री पटवा का निधन देश के लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है, मेरे लिए उनका निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

ऑनलाइन भुगतान करने की जागरूकता तेज़ी से बढ़ी: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई को भी जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा देश में ऑनलाइन भुगतान कैसे करना, इसकी जागरूकता तेज़ी से बढ़ी है। आपके अगल-बगल में जो नौजवान होंगे, आप थोड़ा-सा उनको पूछोगे, वो बता देंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज क्रिसमस के दिन, सौगात के रूप में, देशवासियों को दो योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। एक प्रकार से दो नवतर योजनाओं का आरम्भ हो रहा है। पूरे देश में, गांव हो या शहर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कैशलेस

मुख्य बातें

- देश में ऑनलाइन भुगतान कैसे करना, इसकी जागरूकता तेज़ी से बढ़ी है। आपके अगल-बगल में जो नौजवान होंगे, आप थोड़ा-सा उनको पूछोगे, वो बता देंगे।
- कैशलेस कारोबार 200 से 300% बढ़ा है, जो व्यापारी डिजिटल लेन-देन करेंगे ऐसे व्यापारियों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी।
- हमने कड़े प्रावधानों के साथ बेनामी प्रॉपर्टी कानून को नए सिरे से बनाया है। क़ानून सब के लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनैतिक दल। ।
- आम लोगों द्वारा दी गई जानकारियों के कारण नोट जब्त किए जा रहे हैं और दोषियों को पकड़ा जा रहा है।
- नौजवानों ने स्टार्ट अप से काफ़ी प्रगति की है, लेकिन देश को काले धन, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताक़त से जुड़ना चाहिए।
- आज 25 दिसम्बर को क्रिसमस की सौगात के रूप में, पंद्रह हज़ार लोगों को ड्रॉ सिस्टम से इनाम मिलेगा।
- डिजीधन व्यापार योजना में व्यापारी इस योजना से जुड़ें और अपना कारोबार भी कैशलेस बनाने के लिए ग्राहकों को भी जोड़ें।
- अर्थव्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, इन लोगों को मज़दूरी का पैसा नगद में दिया जाता है, उसके कारण मज़दूरों का शोषण होता है।

क्या है! कैशलेस कारोबार कैसे चल सकता है! बिना कैश खरीदारी कैसे की जा सकती है! चारों तरफ़ एक जिज्ञासा का माहौल बना है। हर कोई एक-दूसरे से सीखना-समझना चाहता है।

श्री मोदी ने कहा कि 25 दिसम्बर को क्रिसमस की सौगात के रूप में, पंद्रह हज़ार लोगों को ड्रा सिस्टम से ईनाम मिलेगा और पंद्रह हज़ार के हर-एक के खाते में एक-एक हज़ार रूपये का ईनाम जाएगा और ये सिर्फ़ आज एक दिन के लिये नहीं है, ये योजना आज से शुरू हो करके 100 दिन तक चलने वाली है। हर दिन, पंद्रह हज़ार लोगों को एक-एक हज़ार रूपये का ईनाम मिलने वाला है। 100 दिन में, लाखों परिवारों तक, करोड़ों रुपयों की सौगात पहुंचने वाली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ये जान करके ख़ुशी होती है कि देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना, ई-पेमेंट कैसे करना, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना, इसकी जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले कुछ ही दिनों में कैशलेस कारोबार, बिना नगद का कारोबार, 200 से 300 प्रतिशत बढ़ा है। इसको बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला कितना बड़ा है इसका अंदाज़ तो व्यापारी बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। जो व्यापारी डिजिटल लेन-देन करेंगे, अपने कारोबार में नगद के बजाय ऑनलाइन पेमेंट की पद्धति विकसित करेंगे, ऐसे व्यापारियों को आयकर में छूट दे दी गई है। ■

उत्तराखंड विकास के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहता: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित विशाल परिवर्तन रैली को संबोधित किया और राज्य के विकास के लिए जनता से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चार धाम यात्रा को जोड़ने वाली 12 हजार करोड़ रुपये की लागत के रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में ऐसी सरकारें आई, जिसने सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को भी पूरा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए यह बस एक राजनीतिक कार्यक्रम होता, जनता-जनार्दन की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने वाला काम होता, तो प्रधानमंत्री बनते ही मैं इसका शिलान्यास कर देता जैसा कि कांग्रेस की पहले की सरकारों और मुख्यमंत्रियों ने किया है, अभी वाले (उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत) तो शायद हर रोज कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा जनता सब कुछ जानती है। बिना बजट के पत्थर गाड़ने का काम करोगे तो योजनायें बनेगी क्या? उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में योजनायें लाने से राजनीति तो चल सकती है, लेकिन समाज नहीं चल सकता, समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए हमने व्यापक रिसर्च और दुनिया भर की कंसल्टेंसी एजेंसियों से डिस्कशन करने के बाद इस योजना की शुरुआत की है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश भर के लोग जब भी इस अद्भुत योजना का अनुभव करेंगे तो उन्हें सुखद अनुभूति होगी और वह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को याद करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है, यदि व्यवस्थाएं ठीक हों, सुविधाएं उपयुक्त हों तो हिन्दुस्तान का कौन सा परिवार उत्तराखंड में चार-पांच दिन नहीं बिताना चाहेगा।

श्री मोदी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन मैंने इस कहावत को बदलने की ठान ली है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी - दोनों पहाड़ के काम आयेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा उत्तराखंड बनायेंगे कि यहां के युवाओं को हिमालय छोड़कर शहरों की तंग गलियों में जिंदगी गुजारने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि 40 सालों से हमारे सेना के जवान हिन्दुस्तान की सरकार से 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग कर रहे थे, लेकिन देश में 40 सालों तक जिस परिवार ने राज किया, उसने कभी भी हमारे सेना के जवानों की मांगों को पूरा करने का सोचा ही नहीं। जब लोक सभा चुनाव सिर पर आया तो उन्होंने इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान कर दिया, जबकि वन रैंक, वन पेंशन का बजट 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है जिसका प्रावधान हमने बजट में कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 500 करोड़ से सेना के जवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया या नहीं? उन्होंने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत अब तक 6600 करोड़ रुपया सेना के जवानों तक पहुंचा दिया गया है, बाकी भी जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा।

40 सालों से हमारे सेना के जवान हिन्दुस्तान की सरकार से "वन रैंक, वन पेंशन' की मांग कर रहे थे, लेकिन देश में 40 सालों तक जिस परिवार ने राज किया, उसने कभी भी हमारे सेना के जवानों की मांगों को पूरा करने का सोचा ही नहीं।

उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंसान पैसे खाता है, यह तो हमने सुना था, लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। उन्होंने कहा कि दुराचार और भ्रष्टाचार ने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया है, हमें इस को बचाना है।प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया, इसे उत्तम उत्तराखंड बनाना हमारी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए दो इंजन की जरूरत है - एक इंजन तो उत्तराखंड की जनता ने दिल्ली में लगा दिया है, दूसरा इंजन देहरादून में भी लगा दीजिये, तो देखते-देखते उत्तराखंड विकास के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा। ■

विमुद्रीकरण: बीते दो महीनों पर एक नजर

अब इसे संशोधित करके लागू कर दिया गया है। जीएसटी इस साल से लागू होने जा रहा है और यह बेहतर अप्रत्यक्ष-कर प्रशासन सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह अधिक सक्षम कानून होने से कर चोरी को रोकने में भी सफल हो सकेगा। उच्च मूल्य वर्ग के मुद्रा नोटों को बंद करना भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

| अरुण जेटली |

प्रधानमंत्री ने उच्च मूल्य वर्ग के लीगल टेंडर को खत्म करने की जो घोषणा की थी उसे दो महीने हो गए हैं। इसके बाद वे नोट विमुद्रीकृत हो गए हैं। देश की 86 प्रतिशत मुद्रा, जो कि जीडीपी का 12.2 प्रतिशत है अगर बाजार से बाहर निकाल जी जाए और उसे नई मुद्रा से परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि इस फैसले के कई महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। बैंकों में लगी लंबी लाइनें अब खत्म हो गई हैं और नई मुद्रा भी तेजी से पहुंच रही है, ऐसे में इस निर्णय के पीछे तर्क और इसके प्रभाव का विश्लेषण करना उचित होगा।

कालेधन के विरुद्ध कदम

नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले ही दिन से यह स्पष्ट कर दिया था कि वह कालेधन और छद्म अर्थव्यवस्था के खिलाफ कदम उठाएगी। इस दिशा में पहला निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कालेधन की जांच के लिए एसआइटी के गठन का था। प्रधानमंत्री ने जी-20 की ब्रिसबेन बैठक में सुझाव दिया था कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तेज करना चाहिए। अमेरिका के साथ की गई व्यवस्था ने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया। राजग सरकार ने स्विटजरलैंड के साथ समझौता किया जो 2019 से लागू होगा जिसके तहत स्विटजरलैंड में भारतीयों की संपत्ति के बारे में सूचनाएं दोनों देश एक दूसरे से साझा करेंगे। वर्ष 1996 से मॉरीसस के साथ दोहरा कराधान निवारण समझौते के नवीनीकरण के लिए वार्ताएं चल रही थी। इस संधि के नवीनीकरण न होने से राउंड ट्रिपिंग को ही प्रोत्साहन मिल रहा था। इसे अब संशोधित व परिवर्धित कर लिया गया है। इसी तरह की संधि साइप्रस और सिंगापुर के साथ भी थी, उन्हें भी संशोधित कर लिया गया है। भारत के बाहर रखी संपत्तियों से संबंधित कालेधन के कानून में 60 प्रतिशत टैक्स और दस साल सजा का प्रावधान है। आय घोषणा योजना 2016 भी 45 प्रतिशत टैक्स के साथ बेहद सफल रही। दो लाख रुपये से अधिक के कैश लेन-देन में पैन कार्ड अनिवार्य कर दिए जाने से कालेधन के जरिए होने वाले खर्च पर अंकुश लगा। बेनामी कानून 1988 में बना था, लेकिन यह कभी लागू नहीं हुआ। अब इसे संशोधित करके लागू कर दिया गया है। जीएसटी इस साल से लागू होने जा रहा है और यह बेहतर अप्रत्यक्ष-कर प्रशासन सुनिश्चित करेगा, साथ ही

यह अधिक सक्षम कानून होने से कर चोरी को रोकने में भी सफल हो सकेगा। उच्च मूल्य वर्ग के मुद्रा नोटों को बंद करना भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

नई सामान्य स्थिति

वर्ष 2015-16 में 125 करोड़ से अधिक की आबादी में से मात्र 3.7 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। इनमें से 99 लाख ने अपनी आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का दावा किया और एक भी पैसे का कर-भुगतान नहीं किया। 1.95 करोड़ करदाताओं ने पांच लाख रुपये से कम आय बतायी। 52 लाख लोगों ने अपनी आय 5 से 10 लाख रुपये के बीच में बतायी। सिर्फ 24 लाख करदाता ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी आय 10 लाख रुपये से अधिक बतायी। इस बात का इससे बेहतर सबूत नहीं हो सकता कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष - दोनों ही टैक्स के मामले में बड़ी संख्या में समाज के लोग कर-कानूनों का पालन नहीं करते। कर कानून का पालन न होने की स्थिति में गरीबी निवारण,राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए जरूरी खर्च के साथ समझौता करना पड़ता है। कई दशकों तक भारत में कुछ लेन-देन कैश में तथा कुछ चैक के जरिए करना आम बात रही है। पक्का और कच्चा खाता कारोबारी भाषा के हिस्से बन गए हैं। कर चोरी को अनैतिक नहीं माना गया, यह जीवन का एक तरीका समझा गया। कई सरकारों ने इसे सामान्य स्थिति समझकर जारी रहने दिया, जबकि इससे व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा था। प्रधानमंत्री का फैसला एक नई सामान्य स्थिति बनाने के लिए है। यह भारत और भारतीयों के व्यय प्रतिरूप को बदलने के लिए है। ऐसे में व्यवस्था में आंशिक व्यवधान होना स्वाभाविक है। सभी सुधारों को लागू करते वक्त कुछ आरंभिक

कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। नोटबंदी से ईमानदारी को लाभ तथा बेइमानों को सजा मिलेगी।

कैश के प्रतिकूल परिणाम

पेपर करेंसी पर कोई ब्याज नहीं मिलता और यह भी मालूम नहीं होता है कि यह किसका है। इसके साथ न तो कोई नाम जुड़ा होता है और न ही कोई इतिहास। वैसे तो अपराध कैश या कैश के बिना भी हो सकता है, लेकिन कैश के चलते अत्यधिक लेन-देन से कालेधन की अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। कर-भुगतान के संबंध में इसका नतीजा 'नॉन-कंप्लायंस' के रूप में होता है जो कर चोरी करने वाले के पक्ष में तथा गरीब एवं वंचित के खिलाफ होता है। हवाला के माध्यम से बड़ी मात्रा में नकदी, टैक्स हैवंस में चली जाती है। कैश में होने वाले लेन-देन की रीयल टाइम निगरानी भी नहीं हो सकती। कैश ऐसा माध्यम है जिससे रिश्वत, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवाद पोषित होता है। विकसित और नैतिक समाज प्रौद्योगिकी की मदद से बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन की ओर बढ़े हैं और उन्होंने अत्यधिक कैश का लेन-देन कम किया है। पेपर करेंसी कई बुराइयों के दरवाजे खोलती है। सरकार जब कर-चोरों से अधिक कर वसूलने में कामयाब रहती है, तो वह अन्य सभी लोगों से कम टैक्स वसूलने की स्थिति में रहती है। कैश के इस्तेमाल को कम करने से आतंकवाद और अपराध भले ही कम न हो, लेकिन यह उन्हें गंभीर चोट तो पहुंचा ही सकती है। कई देशों ने दिखाया है कि कैश का इस्तेमाल अपने आप कम नहीं होता, सरकार को पेपर करेंसी को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने ही पड़ते हैं।

> प्रधानमंत्री और उनके विरोधियों के दृष्टिकोण में एक अंतर स्पष्ट था। प्रधानमंत्री भविष्य के प्रति आशावान, साथ ही उनकी सोच एक अधिक आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी संचालित साफ़-सुथरी अर्थव्यस्था की है।

निर्णय का महत्व

प्रधानमंत्री ने उच्च मूल्य वर्ग के नोट को बंद करने और उन्हें बदलने का जो निर्णय लिया, उसके लिए साहस और शक्ति, दोनों की आवश्यकता होती है। निर्णय का क्रियान्वयन पीड़ादायी रहा। अल्पावधि में इससे असुविधा हो सकती है और इसकी आलोचना भी हो सकती है। मुद्रा की पुनः आपूर्ति के दौरान करेंसी की कमी के चलते आर्थिक गतिविधियों में गिरावट हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर भी बहुत कम समय के लिए क्षणिक प्रभाव पड़ेगा। इस निर्णय को गोपनीय रखते हुए बड़ी मात्रा में पेपर करेंसी छापना और फिर इसे बैंकों, पोस्ट ऑफिसों, बैंक मित्रों और एटीएम के माध्यम से वितरित भी करना था।

महज बैंक में पुराने नोट जमा हो जाने से कालाधन सफेद नहीं हो जाता। कालेधन का रंग सिर्फ इसलिए नहीं बदल जाएगा कि वह बैंक में जमा हो गया। इसके विपरीत हकीकत यह है कि यह धन किसका है इसका अब पता लगाया जा सकेगा। इससे इसकी गुमनामी खत्म हो जायेगी। इस तरह राजस्व विभाग इस धन पर टैक्स वसूलने का अधिकारी होगा। आयकर कानून में पहले ही संशोधन किया जा चुका है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति का काला-धन पकड़ा गया तो उस पर उच्च दर से टैक्स और पेनाल्टी, दोनों वसूली जाएगी।

आज की स्थिति

पीड़ा और असुविधा का दौर अब खत्म हो रहा है। आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। आज बैंकों के पास उधार देने के लिए पहले से काफी अधिक धन उपलब्ध है, क्योंकि बैंकों के पास जमा यह धन कम लागत पर उपलब्ध हुआ है। इसके फलस्वरूप ब्याज दर नीचे आना तय है। ये दोनों बातें पहले हो चुकी हैं। लाखों करोड़ रुपये पहले जो बाजार में पड़े थे, बैंकों के पास आ गए हैं। जिसका पैसा था, उस पर टैक्स लगेगा जिससे वह इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकेगा। बैंकिंग लेन-देन से अर्थव्यवस्था का आकार बढेगा। मध्यावधि और दीर्घावधि में जीडीपी बढ़ेगा और उसमें स्पष्टता आयेगी। बैंकिंग तंत्र में प्रवेश करने वाले धन से और आधिकारिक तौर पर लेन-देन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष-कर अधिक वसूलने का रास्ता साफ होगा। इससे केंद्र और राज्य, दोनों का फायदा होगा। अर्थव्यवस्था को कैश और डिजिटल लेन-देन से फायदा पहुंचेगा।

विपक्ष

इस तरह के एक प्रमुख निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई सामाजिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। स्वतंत्र मीडिया संगठनों द्वारा किए गए सभी जनमत सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिकतर लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। विपक्ष ने संसद का एक पूरा सत्र बाधित कर दिया। उनके विरोध प्रदर्शन अप्रभावी रहे। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचने के उनके अतिशयोक्तिपूर्ण दावे गलत सिद्ध हुए। यह एक त्रासदी है कि कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी ने प्रौद्योगिकी, परिवर्तन और सुधारों का विरोध करने का एक राजनीतिक रुख इख्तियार कर कालेधन की व्यवस्था का साथ दिया।

स्पष्ट अंतर

प्रधानमंत्री और उनके विरोधियों के दृष्टिकोण में एक अंतर स्पष्ट था। प्रधानमंत्री भविष्य के प्रति आशावान, साथ ही उनकी सोच एक अधिक आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी संचालित साफ़-सुथरी अर्थव्यस्था की है। अब वे राजनीतिक चंदे की फंडिंग व्यवस्था की सफाई की बात कर रहे हैं। उनके विरोधी एक नकद प्रभुत्व, नकदी पैदा करने और नकद विनिमय वाली प्रणाली जारी रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का अंतर स्पष्ट है - प्रधानमंत्री अगली पीढ़ी की बात करते हैं, जबकि राहुल गांधी केवल यह सोच रहे हैं कि संसद के अगले सत्र को बाधित कैसे किया जाय। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं)

औपनिवेशिक परंपरा की समाप्ति है बजट सुधार संबंधी घोषणा

यह नई परंपरा की शुरुआत भारत में बजट सुधार की ओर एक बेहतर कदम है, जो अंतिम 70 वर्षों में नदारद थी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में मंत्रालय के बीच सहयोग-समन्वय-संमिलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, साथ ही भारत की मानस को नये साल का नया उपहार है।

| विकाश आनन्द |

कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली नोटों के खात्मे और आर्थिक समरसता के ध्येय से विमुद्रीकरण का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् मोदी सरकार ने बजट सुधार से संबंधित निर्णय लेकर शासन में सुधार के सराहनीय कदम उठाया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बार बजट फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत करने के जगह पर एक महीना पहले ही एक फरवरी को प्रस्तुत करने की घोषणा की है। यह कदम ब्रिटिश भारत अर्थात् गुलामी के समय से चले आ रहे औपनिवेशिक परम्परा को खत्म करता है। इस नये बजट प्रक्रिया में विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक नये वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले ही संसद से पारित हो जाएगा और दूसरा, बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय अलग से रेल बजट लाने की प्रथा को खत्म करके इसका विलय आम बजट में करने का है।

कुल मिलाकर दोनों निर्णय शासन-व्यवस्था और आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह निर्णय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी गति देगा।

बजट प्रक्रिया के परंपरागत अभ्यास में बजट फरवरी के अंतिम दिन में प्रस्तुत किया जाता था। इसके कारण संसद के लिए बजट संबंधी पूरी प्रक्रिया नये वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही पूर्ण करना सम्भव नहीं हो पाता है। चूंकि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार के पास प्रशासनिक-व्यवस्था को जारी रखने आवश्यक वित्तीय संसाधन हो। इस समस्या के तत्कालीन हल के रूप में सरकार लेखानुदान (Vote on Account) की परंपरा को अपनाती थी, जिसके द्वारा सरकार संसद में मत से 3 महीने के व्यय की राशि प्राप्त करती थी। दरअसल, यह एक वर्ष खर्चे का एक भाग होता है।

बजट प्रस्तुत करने के समय को एक महीना अग्रिम करना, वित्तीय विधेयक को नये वित्तीय वर्ष अर्थात् एक अप्रैल के पहले पारित होने को सुनिश्चित करता है तथा 2-3 महीने के लिए 'लेखानुदान' को भी पारित करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सभी केन्द्रीय मंत्रालय, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को नये वित्त वर्ष के प्रारंभ होने के पहले राशि का आवंटन होगा। परिणामस्वरूप योजनाओं, नीतियों का कार्यान्वयन भी समय पर होना संभव हो सकेगा। पहले के परंपरा के अनुसार वित्तीय आवंटन मंत्रालय, विभागों इत्यादि को मई महीने के अंतिम तक मिलता था। यह पुरानी परंपरा योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा थी।

साथ ही आने वाले नये संघीय बजट में योजना बजट और गैर योजना बजट में कोई अंतर नहीं होगा। यह मंत्रालयों का खर्चे संबंधित निर्णय में ज्यादा स्वतंत्र बनाएगी।

इस बजट संबंधित नई परंपरा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि अपने राज्य के बजट को भी इसे नये समय-सारणी के अनुसार कर ले, जिससे राज्य इसका अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।

लोक नीति के विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की बजट प्रक्रिया अग्रिम होने से राज्य को बजट संबंधित विधायी प्रक्रिया नए वित्त वर्ष से पहले करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से योजनाओं पर खर्च समय पर शुरू हो पाएंगे और संघीय बजट पहले लाने से राज्य सरकारों को अपने राज्य के बजट के लिए आगत (input) मिला जाएगा और वे अपने स्कीमों के लिए बजट की बेहतर परिकल्पना कर सकेंगे।

एक तरह यह कदम केन्द्र-राज्य संबंधों का व्यापकता में वृद्धि करता है। अब राज्य सरकार को पूर्ण रूप से 12 महीने वित्तीय आवंटन के विश्लेषण, उपयोग के लिए मिलेगा। परिणामतः केन्द्रीय स्कीमों का राज्य सरकार द्वारा असरदार कार्यान्वयन और निगरानी हो सकेगा।

रेल बजट का आम बजट के साथ शामिल करना भी बजट संबंधित प्रक्रिया को नये वित्तीय वर्ष के पहले पूर्ण करने का ही एक अहम प्रयास है। साथ ही साथ रेलवे पर प्रक्रियागत बोझ को भी कम करना है।

बतौर रेल मंत्री सुरेश प्रभु आम बजट के साथ रेल बजट के विलय से अतिरिक्त पूंजी उगाही में मददगार मिलेंगे। अतिरिक्त मद रेलवे नेटवर्क से जोड़ने और आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करेगा।

> आने वाले नये संघीय बजट में योजना बजट और गैर योजना बजट में कोई अंतर नहीं होगा। यह मंत्रालयों का खर्चे संबंधित निर्णय में ज्यादा स्वतंत्र बनाएगी।

नीति-आयोग के सदस्य विवेक देबराय के अध्यक्षता वाली समिति इस विलय की अनुशंसा करते हुए बताया कि संयुक्त बजट सरकार की संपूर्ण वित्तीय स्थिति को समझने में मददगार साबित होगा। सरकार को बहुतंत्रीय यातायात प्रणाली सड़क-रेल-जलीय ट्रांसपोर्ट के संयुक्त रूप से योजना बनाने में सुगमता होगी। वित्त मंत्रालय को वर्ष के बीच में समीक्षा करने में भी समय सुविधा होगी और संसाधनों का बेहतर आवंटन का मौका भी मिलेगा।

इस प्रकार यह घोषणा भारत में बजट सुधार की ओर एक बेहतर कदम है, जो अंतिम 70 वर्षों में नदारद था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में मंत्रालय के बीच सहयोग-समन्वय-संमिलन (Cooperation-Coordination-Convergence) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है साथ ही भारत की मानस को नये साल का नया उपहार है। ■

पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा, मतगणना 11 मार्च को

चुनाव आयोग ने 4 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा हैं। चुनाव 4 फरवरी से शुरू होंगे और 11 मार्च को नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में पहले चरण के मतदान 4 मार्च को और दूसरे चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 73

सीटों पर मतदान 11 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 67 सीटों पर मतदान 15 फरवरी को होगा। तीसरे चरण में 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होंगे। चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 52 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होंगे। छठे चरण में 49 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होगी। सांतवें और आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी, इसमें 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को पांचों राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ■

भीम मोबाइल ऐप लॉन्च

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को लकी ग्राहक योजना और डिजीधन योजना की शुरुआत की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डिजीधन मेले की शुरुआत के बाद उन्होंने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम भीम रखा। खास बात यह है कि ये ऐप बिना इंटरनेट के चलेगा। प्रधानमंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसी भीम ऐप के इर्द-गिर्द हो जाएगी। ये भीम ऐप दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। सारा कारोबार इसी ऐप के जरिए होगा। ये ऐप 2017 में लोगों के लिए बड़ा नजराना है। अब अंगूठा ही लोगों की पहचान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिन में लाखों परिवारों को इनाम मिलेगा। जिन्हें इस लकी ड्रॉ में इनाम मिला है, उनका मैं अभिनन्दन करता हूं। डिजिटल पेमेंट करने वाले उज्जवल भारत की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर मेगा ड्रॉ होगा, जिसमें करोड़ों रुपये का इनाम दिया जायेगा।

देश में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। दुनिया के लोग गूगल के पास जाएंगे और पूछेंगे कि ये भीम है क्या? शुरुआत में उन्हें महाभारत वाला भीम दिखेगा, पर और गहराई से अंदर जायेंगे तो उन्हें भीम दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि ये भीम सामान्य नहीं है। यह आपके परिवार की आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है।

उन्होंने कहा कि आशावादी लोगों के लिए मेरे पास ढेरों अवसर है। निराशावादी लोगों के लिए कोई दवा नहीं है। प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले अखबारों में खबरें छपती थीं कि कोयला में कितना गया, टूजी में कितना गया और आज लोग कहते हैं कितना आया। आज पैसा जाने की नहीं आने की बात हो रही है। ये बदलाव है। हिन्दुस्तान बदलाव के लिए तैयार है।

'भीम ऐप छोटे व्यापारियों, किसानों, गरीबों, आदिवासियों को ताकत देगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने देश से भ्रष्टाचार और काले-धन को ख़त्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इस वर्ष किये गए विशेष प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देश में डिजिटल ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने हेतु 'BHIM' (Bharat Interface for Money) एप लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि 'भीम' एप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों और गरीबों के उत्थान में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश से काले-धन और भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने का मोदी सरकार का अभियान अब पूर्ण रूप से एक जन-आंदोलन में तब्दील हो गया है, जिसे हम सभी देशवासियों के निरंतर समर्थन की जरूरत है। उन्होंने देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 'भीम' एप डाउनलोड करने और इसे दूसरों को भी डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह ऐप छोटे व्यापारियों, किसानों, गरीबों, आदिवासियों को ताकत देगा। उन्होंने कहा कि भीम लोगों के परिवार की आर्थिक महासत्ता बनने वाली है। उन्होंने कहा कि 'भीम' देश को 2017 का नजराना है। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो सकेगा। तकनीक अमीरों का ही नहीं, गरीबों का भी ख़ज़ाना है। उन्होंने कहा कि अब छोटे व्यापारियों, गरीबों, दुकानदारों को अपने रोजगार को बढ़ाने हेतु लोन लेने के लिए बैंकों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वे बैंकों को अपने मोबाइल के जरिये अपना ट्रांजेक्शन दिखाकर आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को कैशलेस इकॉनमी के जरिये ईमानदारी की राह पर ले जाने के लिए कटिबद्ध है और देश की जनता प्रधानमंत्री जी के इस मुहिम उनके साथ एकजुट खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता की और जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, यह गांव, गरीब और किसान की सरकार है। ■

वर्ष 2016 के कर-संग्रह में भारी वृद्धि

प्रत्यक्ष करों में 12.01 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों में 25 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते अप्रैल-दिसंबर, 2016 के दौरान टैक्स वसूली में भारी वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष करों में 12.01 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कर वसूली में वृद्धि से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं –

प्रत्यक्ष कर

दिसंबर, 2016 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल 5.53 लाख करोड़ रूपये की शुद्ध वसूली हुई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की शुद्ध वसूली से 12.01 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमानों का 65.3 प्रतिशत है।

सकल राजस्व के संदर्भ में कारपोरेट इंकमटैक्स (सीआईटी) तथा व्यैक्तिक इंकमटैक्स (पीआईटी) के संबंध में सीआईटी में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर रही, जबकि पीआईटी में (एसटीटी सहित) 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिफंड समायोजन के बाद सीआईटी वसूली में 4.4 प्रतिशत की सकल वृद्धि रही और पीआईटी संग्रह में 24.6 की वृद्धि रही। अप्रैल-दिसंबर, 2016 में 1,26,371 करोड़ रूपये के रिफंड जारी किए गए जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में जारी रिफंड से 30.5 प्रतिशत अधिक हैं।

दिसंबर, 2016 में एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त के लेखा के बाद 2.82 लाख करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स वसूला गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि से 14.4 प्रतिशत अधिक है। सीआईटी एडवांस टैक्स में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पीआईटी एडवांस टैक्स में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

> दिसंबर, 2016 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल 5.53 लाख करोड़ रूपये की शुद्ध वसूली हुई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की शुद्ध वसूली से 12.01 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमानों का 65.3 प्रतिशत है।

अप्रत्यक्ष कर

दिसंबर, 2016 तक अप्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल 6.30 लाख करोड़ रूपये की शुद्ध राजस्व वसूली हुई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की शुद्ध वसूली से 25 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दिसंबर, 2016 तक अप्रत्यक्ष कर के बजट अनुमानों का 81 प्रतिशत है।

अप्रैल-दिसंबर, 2016 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2.79 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई। पिछले वर्ष में इसी अवधि में 1.95 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इस तरह इसमें 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवा कर में शुद्ध कर वसूली अप्रैल-दिसंबर, 2016 में 1.83 लाख करोड़ रुपये रही। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 1.48 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इस तरह इसमें 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-दिसंबर, 2016 में सीमा शुल्क में 1.67 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 1.60 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इस प्रकार वसूली में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दिसंबर, 2016 के दौरान शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (एआरएम के साथ) में पिछले वर्ष के दिसंबर महीने की तुलना में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर, 2016 में पिछले वर्ष दिसंबर की तुलना में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में क्रमशः 6.3 प्रतिशत, 31.6 प्रतिशत तथा 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर, 2016 में सीमा शुल्क वसूली में कमी दिसंबर, 2015 की तुलना में सोना आयात में 46 प्रतिशत (मात्रा में) कमी आने के कारण हुई। ■

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) एवं देहरादून (उत्तराखंड) में आयोजित परिवर्तन रैलियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

लखनऊ

लखनऊ

लखनऊ

लखनऊ

देहरादून

देहरादून

देहरादून

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लाभ के लिए प्रमुख निर्णयों की घोषणा की

- 12 लाख तक के लोन पर ब्याज में छूट।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे घरों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- रबी फसल के लिए लोन लेने वाले किसानों को 60 दिनों के लिए ब्याज से छूट दी गई है।
- सरकार ने किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड फंड में 20,000 करोड़ रुपये जोड़े।
- 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे डेबिट कार्ड में बदला जाएगा।
- सरकार एनबीएफसी द्वारा दिये गए लोन को भी वहन करेगी और बैंकों से छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट लिमिट उनके टर्नओवर के 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने के लिए कहा है।
- सरकार मुद्रा योजना के लिए आवंटित राशि को भी दोगुना करेगी; दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव और उनके बच्चों के टीकाकरण के लिए उनके बैंक खातों में 6000 रुपये सीधे ट्रांसफर किये जाएंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर 10 साल की अवधि के लिए 8% का एक निश्चित ब्याज दर मिलेगा।